साप्ताहिक

आरएनआई न. :- जेकेएचआईएन/25/ए0631

सबका जम्मू कश्मीर

हिन्दी • वर्षः 2 • अंकः 7 • कठुआ, शनिवार 14 फ़रवरी 2026 • पृष्ठः 16 • मूल्यः 5 रुपए

सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं : प्रधानमंत्री

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय सचिवालय के नए भवन 'विकसित भारत' की दिशा में देश की यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। उन्होंने कहा कि ये भवन केवल प्रशासनिक संरचनाएँ नहीं हैं, बल्कि यह 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं, सपनों और विश्वास का प्रतीक हैं। इन भवनों का निर्माण नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

नए पीएमओ परिसर 'सेवा तीर्थ' तथा केंद्रीय सचिवालय के दो नए भवन 'कर्तव्य भवन 1' और 'कर्तव्य भवन 2' के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक शासन की संरचनाएँ ब्रिटिश काल की सोच और व्यवस्था के अनुरूप बनी रहीं, जिनका उद्देश्य जनता की सेवा के बजाय सत्ता के केंद्रीकरण को दर्शाना था। लेकिन अब समय बदल चुका है और देश की प्रशासनिक व्यवस्था को भी उसी अनुरूप ढाला जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण ब्लॉक और उत्तर ब्लॉक जैसी ऐतिहासिक इमारतें, जिनमें अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा रक्षा, गृह और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संचालित होते रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशासनिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती थीं। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक देश की विरासत का हिस्सा हैं और उनका अपना ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन आज भारत एक नई सोच और नई कार्यशैली के साथ आगे बढ़ रहा है। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों का निर्माण इसी परिवर्तनशील सोच का परिणाम है, जहाँ शासन को 'शक्ति' नहीं बल्कि 'सेवा' के रूप में परिभाषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि इन भवनों में लिए जाने वाले निर्णय किसी सम्राट की इच्छा का प्रतिबिंब नहीं होंगे, बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं को साकार करने का आधार बनेंगे।

■ शेष पेज 2...

जनस्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता : जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष ने सड़े हुए मांस के मुद्दे पर कहा

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू और कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने शुक्रवार को सरकार से खाद्य पदार्थों में मिलावट से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने का आग्रह किया, क्योंकि सदस्यों ने केंद्र शासित प्रदेश में बड़े पैमाने पर सड़े हुए मांस और घटिया पनीर की जब्ती पर चिंता व्यक्त की।

नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के विधायकों सैफुल्लाह मीर, मुबारक गुल, पीरजादा फारूक अहमद शाह और हसनैन मसूदी के एक संयुक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने विधानसभा को सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, दिसंबर 2025 तक, जम्मू और कश्मीर में 1,676 निरीक्षणों के दौरान 29.19 लाख रुपये से अधिक मूल्य का 12,183.5 किलोग्राम से अधिक सड़ा हुआ मांस नष्ट किया गया।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि जम्मू क्षेत्र में 16.32 लाख रुपये से अधिक मूल्य का 7,665 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त किया गया है। इटू ने बताया कि मांस और मांस उत्पादों के कुल 144 नमूने और पनीर के 173 नमूने जम्मू और कश्मीर के भीतर और बाहर की खाद्य प्रयोगशालाओं में विश्लेषण के लिए भेजे गए थे।

सभी 144 मांस और मांस उत्पाद नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिनमें से एक को

■ शेष पेज 2...

ज़ोनिंग सुधार और डेटा सत्यापन को लेकर जम्मू मास्टर प्लान-2032 रुका हुआ : मुख्यमंत्री उमर

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू और कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भूमि उपयोग क्षेत्र निर्धारण में सुधार, राजस्व गांवों के साथ सीमा निर्धारण, जनता की आपत्तियों और सुझावों को शामिल करने और विभिन्न विभागों से डेटा एकत्र करने और सत्यापन के कारण जम्मू मास्टर प्लान-2032 की अंतिम मंजूरी में देरी हुई है।

परिणामस्वरूप, जम्मू मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 652.33 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 777.84 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जिसमें 350 राजस्व गांव शामिल हैं। विधानसभा में भाजपा विधायक चंद्र प्रकाश के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू मास्टर प्लान-2032 का संशोधन, जो 2021 में शुरू हुआ था, वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है। अब्दुल्ला ने लिखित उत्तर में कहा, ध्वतिम मंजूरी में देरी के कारण गलत भूमि उपयोग क्षेत्र निर्धारण और राजस्व गांवों के साथ सीमा निर्धारण में सुधार, जनता की आपत्तियों और सुझावों को शामिल करना और राजस्व और वन विभागों से लंबित इनपुट सहित विभिन्न विभागों से डेटा प्राप्त करने और सत्यापित करने में लगने वाला समय है। उन्होंने बताया कि जम्मू मास्टर प्लान-2032 की समीक्षा के लिए जम्मू और कश्मीर विकास

■ शेष पेज 2...

बजट सत्र का तूफानी पहला चरण समाप्त; लोकसभा की बैठक अवकाश के बाद 9 मार्च को फिर से होगी

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण पर तीखी बहस के साथ समाप्त हुआ बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार को समाप्त हो गया और सदन अब 9 मार्च को पुनः बैठेगा।

तीन सप्ताह के अवकाश के दौरान स्थायी समितियां केंद्रीय बजट में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को दिए गए आवंटन की जांच करेंगी। इससे पहले दिन में, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा नारे लगाने के बाद सदन को एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था। विपक्षी सदस्य भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का भी विरोध कर रहे थे।

बजट सत्र का पहला भाग 28 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मु के संबोधन के साथ शुरू हुआ था। 2 फरवरी की दोपहर से ही लोकसभा में नाटकीय दृश्य देखने को मिले और बार-बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, जब अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 2020 के भारत-चीन संघर्ष से संबंधित नरवणे के संस्मरण के अंशों का पाठ करने से रोक दिया। आने वाले

■ शेष पेज 2...

सरकार ने लोकसभा को बताया कि 2016 से अब तक मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ 8,600 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : लोकसभा को शुक्रवार को बताया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के कार्यालय को 2016 से अब तक मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ 8,600 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

लिखित जवाब में, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2016 से 2025 के बीच मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ 8,639 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सीजेआई के कार्यालय को

■ शेष पेज 2...

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

शेष पेज 1 से.....

सेवा तीर्थ, कर्तव्य...

यह परिवर्तन केवल भवनों का नहीं, बल्कि शासन की संस्कृति का है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि नई कार्यस्थल संरचना से मंत्रालयों के बीच समन्वय बढ़ेगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और तकनीक के अधिक उपयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुशासन, सामाजिक न्याय और नागरिक सुविधा के समन्वित मॉडल पर आधारित है। नए भवनों में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएँ, हरित ऊर्जा के उपयोग की व्यवस्था और आधुनिक कार्यस्थल संस्कृति को ध्यान में रखकर डिजाइन तैयार किया गया है। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि नागरिकों को सरक.ारी सेवाओं के लिए कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई–गवर्नेंस और एकीकृत कार्य प्रणाली के माध्यम से आम नागरिकों तक सेवाएँ शीघ्र और सरलता से पहुँचाई जाएँगी। सेवा तीर्थ का नामकरण भी इसी भावना को दर्शाता है कि शासन एक तीर्थ के समान पवित्र दायित्व है, जहाँ सेवा सर्वोच्च है।

उन्होंने यह भी कहा कि बीते वर्षों में भारत ने बुनियादी ढाँचे के विकास में ऐतिहासिक प्रगति की है। आधुनिक संसद भवन, नए राजपथ का कर्तव्य पथ में परिवर्तन और अब पीएमओ व केंद्रीय सचिवालय के नए भवन इस व्यापक परिवर्तन का हिस्सा हैं। यह सब मिलकर एक ऐसे भारत की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जो अपनी विरासत का सम्मान करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढाल रहा है।

प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि यह परिसर केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल नहीं होगा, बल्कि यह देश की विकास यात्रा का केंद्र बनेगा। यहाँ से लिए जाने वाले निर्णय आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को आकार देंगे। उन्होंने सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों को देश की जनता को समर्पित करते हुए विश्वास जताया कि यह नया अध्याय भारत को वैश्विक मंच पर और अधिक सशक्त बनाएगा तथा विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में उसकी गति को तेज करेगा।

जनस्वास्थ्य से समझौता...

निम्न गुणवत्ता का और 17 को असुरक्षित पाया गया है। इसी तरह, पनीर के 173 नमूनों में से 157 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मंत्री ने बताया कि इनमें से 47 नमूनों को निम्न गुणवत्ता का और एक को असुरक्षित पाया गया है।

इतू ने केंद्र शासित प्रदेश के दोनों खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (श्रीनगर और जम्मू में स्थित) में तकनीकी कर्मचारियों की कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रत्येक में स्वीकृत 19 पदों के मुकाबले 11 पद रिक्त हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद 22 रिक्त पदों को भर्ती एजेंसियों को भेजा जाएगा। मंत्री ने कहा

कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करके, अधिसूचित प्रयोगशालाओं के माध्यम से नमूने एकत्र करके और उनकी जांच करके तथा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ लाइसेंस निलंबित या रद्द करने, जुर्माना लगाने और अभियोजन सहित सख्त कार्रवाई करके प्रवर्तन को तेज कर दिया है।

उन्होंने कहा कि श्रीनगर और जम्मू सहित विभिन्न जिलों में असुरक्षित मांस और मांस उत्पादों की बिक्री में शामिल पाए गए 18 खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिनमें से अधिकांश मामले वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं।

मुख्य प्रश्न के पूरक प्रश्न में, सीपीआई (एम) विधायक एम.वाई. तारिगामी और भाजपा के बलवंत सिंह मनकोटिया ने सुझाव दिए और प्रवर्तन कार्रवाई, अंतर–विभागीय समन्वय, कानूनी अनुवर्ती कार्रवाई और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपायों पर अधिक विवरण मांगा। मंत्री ने कई कमियों को स्वीकार किया, जिनमें सख्त कार्रवाई लागू करने के लिए पुलिस पर सरकार का अधिकार न होना भी शामिल था। इस पर अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए उनसे खाद्य सुरक्षा और खाद्य उत्पादों से संबंधित कानून में आवश्यक संशोधन करके इन खामियों को दूर करने का आग्रह किया। अध्यक्ष ने कहा,

"यदि आपको लगता है कि मौजूदा प्रावधान इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो सरकार अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक क्यों नहीं लाती? सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए और खाद्य सुरक्षा विभाग की शक्तियों को बढ़ाना चाहिए तथा उन शक्तियों को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए ताकि इस संबंध में कोई शिकायत न आए।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जन स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता।

मीर ने इस मुद्दे को "जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण" बताया। एनसी विधायक ने सवाल उठाया कि इस तरह की खेप टोल चौकियों को कैसे पार करती है और पुलिस, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और नगर निकायों की भूमिका पर स्पष्टता मांगी।

शाह, मसूदी और गुल ने भी नीति कार्यान्वयन में प्रणालीगत कमियों पर चिंता व्यक्त की, जिसमें कर्मचारियों की कमी, अपर्याप्त स्थानीय परीक्षण बुनियादी ढांचा और बाहरी प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी शामिल है। उन्होंने मिलावट में शामिल व्यवसायों को सील करने सहित कड़े दंडात्मक प्रावधानों की मांग की।

तारिगामी ने शक्तियों के स्पष्ट विभाजन और पुलिस के साथ बेहतर समन्वय की मांग करते हुए सुझाव दिया कि एक विशेष प्रवर्तन तंत्र पर विचार किया जा सकता है।

मनकोटिया ने सरकार से आग्रह किया कि वह निजी सदस्य विधेयक की प्रतीक्षा करने के बजाय विधानसभा के वर्तमान सत्र में ही संशोधन लाए।

ज़ोनिंग सुधार और...

अधिनियम, 1970 की धारा 3 के तहत 18 अक्टूबर, 2021 को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा, "जम्मू विकास प्राधिकरण और नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के बीच 28 जनवरी, 2021 को संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए थे।" उन्होंने आगे बताया कि शहरी योजनाकारों और जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया और उपग्रह चित्रों और मौजूदा भूमि उपयोग सर्वेक्षणों का उपयोग करके आधार मानचित्र तैयार किए गए। उन्होंने कहा, "अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान के माध्यम से यातायात और परिवहन सर्वेक्षण और एक सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित किया गया, जिसके बाद विस्तृत क्षेत्रीय विश्लेषण और तकनीकी रिपोर्ट तैयार की गई।" उन्होंने बताया कि योजना सीमा को संशोधित किया गया और स्थानीय योजना क्षेत्र 652.33 वर्ग किमी से बढ़कर 777.84 वर्ग किमी हो गया, जिसमें 350 राजस्व गांव शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि संशोधित मसौदा मास्टर प्लान 14 अक्टूबर, 2024 से 3 जनवरी, 2025 तक 80 दिनों के लिए सार्वजनिक किया गया था, इस दौरान 143 आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए। उन्होंने कहा, "16 जनवरी, 2025 के सरकारी आदेश के तहत एक जांच बोर्ड का गठन किया गया था और 23 जनवरी, 2025 को जन सुनवाई आयोजित की गई थी।" उन्होंने आगे कहा कि जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि, भाजपा विधायक युदवीर सेठी ने आपत्ति जताई कि सरकार के डेढ़ साल सत्ता में रहने के बावजूद जम्मू मास्टर प्लान–2032 को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा, "जब सरकार ने पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो मंत्रिमंडल इस पर क्यों बैठा है? वे इसे मंजूरी देने में विफल रहे हैं।"

बजट सत्र का...

दिनों में सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन और नाटकीय दृश्य देखने को मिले, जिसके परिणामस्वरूप सात कांग्रेस और एक सीपीआई–एम सदस्य को बजट सत्र के शेष भाग के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। इन सदस्यों पर अधिकारियों की मेजों पर चढ़ने और अध्यक्ष पर कागज़ फाड़ने जैसे दुर्व्यवहार का आरोप था। अप्रिय स्थिति की आशंका से अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरा.ेध किया कि जब उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देना हो, तब वे लोकसभा में उपस्थित न हों। प्रधानमंत्री ने सदन में भाषण नहीं दिया, लेकिन बाद में राज्यसभा में इसी तरह की बहस में भाग लिया। विपक्ष ने बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने का नोटिस भी प्रस्तुत किया। नैतिक आधार पर, बिरला ने अपने निष्कासन से संबंधित मामले के निपटारे तक सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता न करने का निर्णय लिया। अध्यक्ष पद से बिरला को हटाने का प्रस्ताव 9 मार्च से शुरू होने वाले सत्र के दूसरे भाग में सदन में आने की संभावना है। केंद्रीय बजट पर बहस शुरू होने से पहले गांधी के बोलने पर अड़े रहने के कारण सदन में हंगामा हुआ और बार–बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। व्यथित बिरला ने सदन को बताया कि पिछले सप्ताह तक व्यवधानों के कारण सदन का 19 घंटे और 13 मिनट का समय बर्बाद हुआ। बाद में, केंद्रीय बजट पर बहस में भाग लेते हुए, गांधी ने अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करते समय भारत के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप सरकार पर लगाया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के नेता द्वारा लगाए गए आरा.ेपों का खंडन करते हुए कहा कि यह पिछली कांग्रेस सरकार थी जिसने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में देश को बेच दिया था।

कानूनी स्पष्टता लाने के उद्देश्य से औद्योगिक संबंध संहिता में संशोधन करने वाला विधेयक संसद के सत्र के पहले भाग में पारित हो गया।

यह विधेयक 2020 की औद्योगिक संबंध संहिता द्वारा प्रतिस्थापित कुछ कानूनों की निरंतरता को लेकर भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी अनावश्यक जटिलता से बचने में सहायक होगा।

यह बजट सत्र में संसद द्वारा प्रस्तुत और पारित किया गया पहला विधेयक है। बजट सत्र 2 अप्रैल को समाप्त होगा।

सरकार ने लोकसभा...

मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतें (1,170) 2024 में प्राप्त हुईं।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का निपटारा न्यायपालिका द्वारा एक ष्आंतरिक तंत्रष के माध्यम से किया जाता है।

उन्होंने याद दिलाया कि मई 1997 में, सर्वोच्च न्यायालय ने दो प्रस्तावों को अपनाया था – ष्न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथनष, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ न्यायिक मानकों और सिद्धांतों को निर्धारित करता है; और ष्आंतरिक प्रक्रियाष, जो उन न्यायाधीशों के खिलाफ उचित उपचारात्मक उपाय करती है जो न्यायिक जीवन के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मूल्यों का पालन नहीं करते हैं, जिनमें ष्न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथनष भी शामिल है।

उच्च न्यायपालिका की स्थापित आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं।

इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के विरुद्ध शिकायतें मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को भेजी जाती हैं जो ऐसी शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं।

भाजपा विधायक के बयान पर कि कश्मीर घाटी के लोग जम्मू में जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, सदन में हंगामा मच गया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू और कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को उस समय हंगामा मच गया जब भाजपा सदस्य विक्रम रंधावा ने दावा किया कि कश्मीर घाटी के लोगों ने जम्मू शहर में जमीन पर अतिक्रमण किया है।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान रंधावा के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए समाज कल्याण मंत्री सकीना इटू ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, तहसील बहू में 688 कनाल (8 कनाल 1 एकड़ के बराबर) और 17 मरला (160 मरला 1 एकड़ के बराबर) तथा तहसील जम्मू दक्षिण में 579 कनाल जमीन पर अवैध अतिक्रमण है।

मुख्यमंत्री की ओर से जवाब देते हुए इटू ने कहा, "ये अतिक्रमण पुराने हैं और सार्वजनिक परिसर (अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करना) अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार इन्हें हटाया जा रहा है।"

मंत्री ने बताया कि जनवरी 2025 से अब तक तहसील बहू और जम्मू दक्षिण में कुल 34 अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) की 140 कनाल और 11 मरला जमीन वापस ली गई है।

रंधावा ने आरोप लगाया कि घाटी के लोगों की बस्तियां जेडीए और सरकार की अतिक्रमित जमीन पर बनी हैं और अधिकारी अतिक्रमण हटाने में विफल रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि इन बस्तियों में से 90 प्रतिशत कश्मीर घाटी के लोगों की हैं।

उन्होंने कहा, "सरकार इसकी जांच करे और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करे। जम्मू में जेडीए की 16,000 कनाल से अधिक जमीन पर अतिक्रमण है।" उन्होंने आगे कहा, "हमें कश्मीरियों द्वारा जम्मू में जमीन खरीदकर घर बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें सरकारी जमीन पर घर नहीं बनाने चाहिए।"

रंधावा के ये दावे सत्ताधारी राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों को रास नहीं आए।

दिल्ली-एनसीआर में टिकाऊ परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के विस्तार से इसे और मजबूत बनाया जाएगा

सबका जम्मू कश्मीर

दिल्ली–एनसीआर में वायु गुणवत्ता निगरानी ढांचे को टिकाऊ परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों (सीएएक्यूएमएस) के नेटवर्क के व्यवस्थित विस्तार के माध्यम से सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि क्षेत्र भर में व्यापक कवरेज, बेहतर डेटा विश्वसनीयता और वायु प्रदूषण का ठोस वैज्ञानिक मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता निगरानी को बढ़ाना और दिल्ली–एनसीआर में प्रभावी वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए साक्ष्य–आधारित नीतिगत उपायों का समर्थन करना है।

वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को सुदृढ़ करने के सतत प्रयासों के अंतर्गत, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) दिल्ली–एनसीआर में 27 नए सीएक्यूएम (6 दिल्ली में, 7 हरियाणा (एनसीआर) में, 4 राजस्थान (एनसीआर) में और 10 उत्तर प्रदेश (एनसीआर) में) के विस्तार की स्थिति की समीक्षा कर रहा है। ये नए केंद्र क्षेत्र की संबंधित एजेंसियों द्वारा संचालित 84 निगरानी केंद्रों (40 दिल्ली में, 22 हरियाणा–एनसीआर में, 4 राजस्थान–एनसीआर में और 18 उत्तर प्रदेश–एनसीआर में) के मौजूदा नेटवर्क के अतिरिक्त हैं। दिल्ली–एनसीआर में स्थापित इन 27 नए सीएक्यूएम में सेरू दिल्ली में 6 सीएएक्यूएमएस स्थापित किए गए हैं; हरियाणा (एनसीआर) में 07 नए सीएएक्यूएमएस, राजस्थान (एनसीआर) में 04 और उत्तर प्रदेश (एनसीआर) में 10 सीएएक्यूएमएस की स्थापना प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में जारी विस्तार के अलावा, दिल्ली–एनसीआर में वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क के भविष्य के विस्तार के लिए वैज्ञानिक मानदंडों पर भी विस्तारपूर्वक विचार–विमर्श किया गया।

इस बात पर जोर दिया गया कि निगरानी घनत्व में जनसंख्या वितरण, आवासीय, यातायात, औद्योगिक और पृष्ठभूमि क्षेत्रों जैसी भूमि उपयोग विशेषताओं, शहरी निरंतरता और उपनगरीय क्षेत्रों के तीव्र विस्तार को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। ग्रिड–आधारित स्थानिक कवरेज की आवश्यकता पर भी विचार किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली–एनसीआर को प्रभावित करने वाले प्रदूषकों के क्षेत्रीय परिवहन और आधारभूत वायु गुणवत्ता स्तरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए पृष्ठभूमि और सीमावर्ती स्टेशनों की भी आवश्यकता है।

इसके अनुसार, दिल्ली और आसपास के शहरों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत आदि के लिए मौजूदा जनसंख्या–आधारित मानदंडों के अतिरिक्त, प्रत्येक 25 वर्ग किलोमीटर (5 किमी × 5 किलोमीटर ग्रिड) में लगभग एक वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित करने के लिए मानदंड तैयार किए गए हैं, जबकि अन्य जिला मुख्यालयों और शहरों में प्रत्येक 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक केंद्र होगा।

शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में निगरानी कवरेज को प्रदूषण के अंतर्वाह और बहिर्वाह का आकलन करने और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता पर शहरी फैलाव के प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।

2019–20 से 2023–24 तक कंपनियों का सीएसआर व्यय 1.44 लाख करोड़ अधिक

सबका जम्मू कश्मीर

सरकार, कंपनियों द्वारा एमसीए 21 रजिस्ट्री में दर्ज कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय का एक केन्द्रीय डेटाबेस रखती है। एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा दर्ज किए गए सीएसआर व्यय से संबंधित सभी डेटा, जिसमें राज्यवार, वर्षवार, कंपनीवार और परियोजनावार डेटा शामिल है, ॣबेत.हवअ.पद पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, निर्णय लेने, उन्हें क्रियान्वित करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति के निर्माण, सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय के प्रमाणीकरण और वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय के लेखापरीक्षा आदि से संबंधित मौजूदा कानूनी प्रावधान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के तंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी जिसका पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत सीएसआर दायित्व 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उसे एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से अपने उन सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन कराना होगा जिनका व्यय एक करोड़ रुपये या उससे अधिक है और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हों। सीएसआर गतिविधियों, प्रभाव मूल्यांकन आदि का विवरण सभी कंपनियों द्वारा 'सीएसआर से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट' में, जिसमें सीएसआर से संबंधित वार्षिक कार्य योजना भी शामिल है, कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

सीएसआर कानूनी ढांचे में सीएसआर निधि के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है और अधि. नियम की धारा 135 (5) के अनुसार, सीएसआर की अनिवार्यता वाली कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत अधिनियम की अनुसूची टप्प में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों पर खर्च करना होगा। एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक के विकास से जुड़े सीएसआर व्यय इस प्रकार हैं।

रक्षा सचिव की सेशेल्स के विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्री और रक्षा बल प्रमुख से मुलाकात

सबका जम्मू कश्मीर

रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की 10 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में सेशेल्स गणराज्य के विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्री श्री बैरी फॉरे और सेशेल्स रक्षा बल प्रमुख मेजर जनरल माइकल एंसेल्मे मार्क रोसेट से मुलाकात हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत और सेशेल्स के बीच बढ़ते रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की और रक्षा सहयोग सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

दोनों पक्षों ने भारतीय और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटी – 2026 तथा क्षमता निर्माण पहल का स्वागत किया और इन गतिविधियों के दायरे विस्ध्तृत करने और गहन बनाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, जलविज्ञान, पोत और विमानों के एक दूसरे के यहां आवागमन, रक्षा प्रतिनिधिमंडल के दौरे और समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई। रक्षा सचिव ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय बेड़े की समीक्षा और अगले सप्ताह विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले द्विवार्षिक, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, 2026 मिलान अभ्यास में सेशेल्स की भागीदारी का स्वागत किया।

दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र प्रगति पर आधारित महा. सागर योजना पर भी चर्चा की जो सभी क्षेत्रों में समावेशी, सहयोगात्मक और सतत सुरक्षा और विकास पर भारतीय दृष्टिकोण है। दोनों पक्षों ने साझा चुनौतियों, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी के क्षेत्र में, सहयोगात्मक रूख के महत्व पर बल दिया। उन्होंने भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग के भविष्य के अवसरों पर भी बातचीत की जिसमें दीर्घकालिक साझेदारी द्वारा क्षमता निर्माण में निरंतर सहयोग पर केंद्रित प्रमुख सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण पर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोगों को बस्तर पंडुम त्योहार के विशेष आयोजन पर बधाई दी

सबका जम्मू कश्मीर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 7 से 9 फरवरी तक मनाए गए श्बस्तर पंडुमश उत्सव के लिए छत्तीसगढ़वासियों को हार्दिक बधाई दी है। इस उत्सव के दौरान बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और आदिवासी विरासत का भव्य प्रदर्शन किया गया। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

श्री मोदी ने कहा, "पहले जब भी बस्तर का नाम लिया जाता था तब माओवाद, हिंसा और विकास में पिछड़ेपन की छवि मन में आती थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। आज बस्तर न केवल अपने विकास के लिए बल्कि यहां के लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास के लिए भी जाना जाता है। मेरी यही कामना है कि आने वाला समय इस क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सांस्कृतिक गौरव की भावना से परिपूर्ण हो।"

केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह की ओर से ग पर किए गए एक पोस्ट के उत्तर में श्री मोदी ने कहारू

7 से 9 फरवरी के बीच छत्तीसगढ़ में 'बस्तर पंडुम' का विशेष आयोजन किया गया। इस उत्सव के दौरान बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जनजातीय विरासत का भव्य रूप दिखा। इस प्रयास से जुड़े अपने सभी परिवारजनों को मेरी हार्दिक बधाई। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

पहले जब बस्तर का नाम लिया जाता था तो माओवाद, हिंसा और विकास में पिछड़ेपन की छवि उभरती थी। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज बस्तर विकास के साथ–साथ स्थानीय लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है। मेरी यही कामना है कि यहां का आने वाला समय शांति, प्रगति और सांस्कृतिक गौरव की भावना से परिपूर्ण हो।ष

जम्मू-कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपये के अप्रयुक्त पड़े ऋणों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं

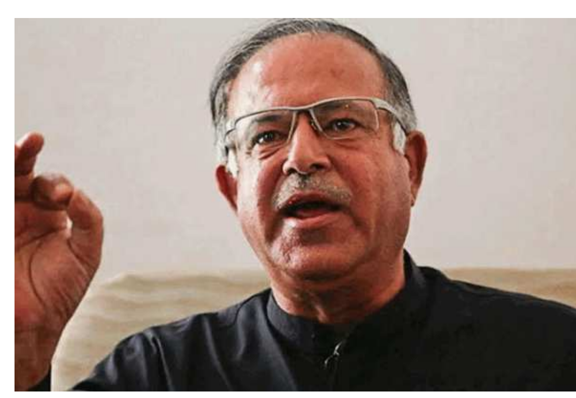

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष तारिक क़रा ने राज्यों के पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआइ) योजना के तहत नए ऋण लेने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपये अभी भी खर्च नहीं किए गए हैं।

विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए, क़रा ने कहा कि अब तक बजट का केवल लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा ही पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया है।

उन्होंने पूछा कि जब पर्याप्त धनराशि पहले से ही उपलब्ध है तो अतिरिक्त ऋण लेने का प्रयास क्यों किया जा रहा है।

ष्यदि इतनी बड़ी राशि अप्रयुक्त रहती है, तो नए ऋण लेने का क्या औचित्य है?ष क़रा ने राजकोषीय प्रबंधन और विकास प्राथमिकताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा।

पीसीसी प्रमुख ने कहा कि कर्ज बढ़ाने से जम्मू–कश्मीर पर अति. रिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। उन्होंने मौजूदा निधियों के उपयोग और विकास परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की योजना पर भी स्पष्टता मांगी।

क़रा ने कहा कि पूंजीगत व्यय अवसंरचना विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्होंने आवंटित संसाधनों के बेहतर उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

वैष्णो देवी रोपवे को 2024 में उपराज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई, कैबिनेट द्वारा नहीं : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रस्तावित रोपवे परियोजना को लेकर चल रही राजनीतिक बहस और भ्रम के बीच जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस परियोजना को वर्ष 2024 में तत्कालीन उपराज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस परियोजना को न तो राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है और न ही यह प्रशास. निक परिषद का निर्णय है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद रोपवे परियोजना को लेकर चल रहे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है।

विधानसभा के सदन में इस विषय पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने स्वयं इस मामले से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड की व्यक्तिगत रूप से जांच की है। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों की गहन समीक्षा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मंत्रिमंडल द्वारा रोपवे परियोजना को मंजूरी दिए जाने का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में एक सदस्य ने यह कहा था कि मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बयान करते हैं।

उमर अब्दुल्ला ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, "मैंने रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी है। यह प्रशासनिक परिषद का निर्णय भी नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि यह जरूरी है कि सदन और जनता के सामने सही तथ्य रखे जाएं, ताकि किसी तरह का भ्रम या गलतफहमी न फैले। मुख्यमंत्री के अनुसार, रोपवे परियोजना से जुड़ी जानकारी को लेकर गलत दावे किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को गुमराह किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनी हुई सरकार के गठन से पहले, सितंबर 2024 में तत्कालीन उपराज्यपाल द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय राज्य में निर्वाचित सरकार मौजूद नहीं थी और प्रशासनिक व्यवस्था उपराज्यपाल के अधीन थी। ऐसे में इस निर्णय की जिम्मेदारी न तो वर्तमान सरकार पर डाली जा सकती है और न ही इसे मंत्रिमंडल के निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर भावनात्मक बयानबाजी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सदन और जनता को इस विषय पर गुमराह किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी याद दिलाया कि एक सदस्य ने भावुक क्षण में एक दिन पहले इस्तीफा देने की धमकी दी थी। उन्होंने संकेत दिया कि इस तरह के बयान तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में दिए गए हैं और इससे राजनीतिक माहौल अनावश्यक रूप से गर्म हो रहा है।

मुख्यमंत्री का यह बयान माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक बलदेव राज शर्मा के उस दावे के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मंत्रिमंडल ने रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। शर्मा ने यह भी कहा था कि यदि उनका यह दावा गलत साबित होता है तो वे अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इस बयान के बाद विधानसभा के भीतर और बाहर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी।

माता वैष्णो देवी मंदिर देश के सबसे प्रमुख और श्रद्धालुओं द्वारा सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रोपवे परियोजना को एक ऐसी सुविधा के रूप में देखा जा रहा है, जिससे विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगों और अस्वस्थ श्रद्धालुओं को यात्रा में सहूलियत मिल सके। हालांकि इस परियोजना को लेकर स्थानीय स्तर पर और विभिन्न संगठनों द्वारा पर्यावरण, आजीविका और धार्मिक परंपराओं से जुड़े सवाल भी उठाए जाते रहे हैं।

राजनीतिक दृष्टि से भी रोपवे परियोजना एक संवेदनशील मुद्दा बन चुकी है। जहां एक ओर इसे विकास और सुविधा से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ वर्ग इसे परंपरागत यात्रा व्यवस्था और स्थानीय हितों के लिए चुनौती मानते हैं। ऐसे में परियोजना को किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी गई, यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि वर्तमान चुनी हुई सरकार इस निर्णय की जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस तरह के मामलों में तथ्यों की पुष्टि किए बिना बयान देना न केवल सदन की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि जनता में गलत संदेश भी देता है। मुख्यमंत्री ने यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार पारदर्शिता और तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहती है।

इस पूरे घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि जम्मू और कश्मीर में पूर्ववर्ती प्रशासनिक निर्णयों और वर्तमान राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच अंतर को समझना जरूरी है। उपराज्यपाल के कार्यकाल में लिए गए निर्णयों को मौजूदा सरकार से जोड़ना कई बार भ्रम और विवाद का कारण बन जाता है। मुख्यमंत्री के अनुसार, ऐसे मुद्दों पर स्पष्टता लाना सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बना रहे।

फिलहाल रोपवे परियोजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री के बयान ने जहां एक ओर स्थिति को स्पष्ट किया है, वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक के दावे और इस्तीफे की चेतावनी ने इस मुद्दे को और भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब यह देखना होगा कि आगे इस परियोजना को लेकर सरकार क्या रुख अपनाती है और क्या इस पर पुनर्विचार या नए सिरे से चर्चा की कोई प्रक्रिया शुरू होती है।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह बयान न केवल रोपवे परियोजना की मंजूरी से जुड़े तथ्यों को सामने लाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जम्मू और कश्मीर की राजनीति में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को लेकर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर आगे होने वाली राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां यह तय करेंगी कि माता वैष्णो देवी रोपवे परियोजना का भविष्य किस दिशा में जाता है।

जम्मू-कश्मीर सरकार विधायकों के निजी सहायकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव की जांच कर रही है

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू-कश्मीर सरकार विधायकों के साथ कार्यरत निजी सहायकों के मासिक मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस विषय को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लंबे समय से निजी सहायकों द्वारा अपने वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी, जिसे अब औपचारिक रूप से सरकार के समक्ष रखा गया है और संबंधित विभागों में इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस नेता और विधायक तारिक हमीद कर्रा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सामने आई। कर्रा ने सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा था कि क्या यह सही है कि विधायकों के साथ काम करने वाले निजी सहायकों ने अन्य सांसदों के कर्मचारियों के समान अपने मासिक मानदेय और टीए/डीए जैसे भत्तों में वृद्धि की मांग रखी है। उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि यदि ऐसा प्रस्ताव वास्तव में सरकार के पास आया है, तो इस पर विचार करने की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए कोई समय-सीमा तय की गई है या नहीं।

सरकार की ओर से दिए गए लिखित जवाब में बताया गया कि माननीय विधायकों के निजी सहायकों के मासिक मानदेय में वृद्धि के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से भेजा गया है, जिसे फिलहाल वित्त विभाग में विचाराधीन रखा गया है। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि प्रस्ताव की जांच की जा रही है और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय लिया जाएगा। निजी सहायकों की भूमिका विधायकों के कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे न केवल विधायकों के दैनिक कार्यालयीन कार्यों को संभालते हैं, बल्कि जनता से जुड़े मामलों, पत्राचार, बैठकों के समन्वय और विभिन्न सरकारी विभागों से संपर्क बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। विधानसभा सत्रों के दौरान भी निजी सहायकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां होती हैं, जिनमें दस्तावेजों की तैयारी, प्रश्नों और प्रस्तावों से संबंधित जानकारी जुटाना तथा विधायकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना शामिल है।

भारत उद्यम स्तर पर एआई के उपयोग में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है; सुरक्षा संबंधी जोखिम मंडरा रहे हैं

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : क्लाउड सिक्योरिटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जेडस्केलर की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को अपनाने में एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है, और उद्यम एआई/एमएल लेनदेन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है।

ज़स्केलर थ्रेटलैब्ज़ 2026 एआई सिक्योरिटी रिपोर्ट में जारी किए गए ये निष्कर्ष, बहुचर्चित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से एक सप्ताह पहले आए हैं। वैश्विक तकनीकी नेताओं, नीति निर्माताओं और नवोन्मेषकों का जमावड़ा होने की उम्मीद वाला यह शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी तक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाला है और इसमें एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग, ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई और क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमोन जैसे वैश्विक तकनीकी नेता शामिल होंगे।

लोकसभा से खिसके, राज्यसभा में बमके : बताया कुछ नहीं, छुपाया बहुत कुछ

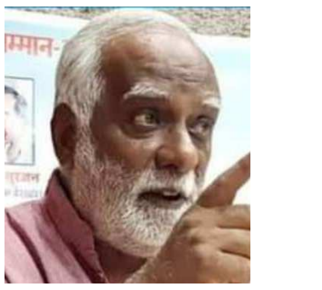

पिनरायी विजयन, अनुवाद : संजय पराते

भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए प्रस्तुत किये गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देने प्रधानमंत्री नहीं आये। यह सिर्फ रस्म या परम्परा भर का सवाल नहीं है। भारत ने जिस संसदीय पद्वत्ति को चुना है, उसमे राष्ट्रपति का अभिभाषण एक महत्वपूर्ण वक्तव्य होता है। यह उस पद पर बैठे व्यक्ति का निजी संबोधन नहीं होता रू असल में तो राष्ट्रपति के ज्यादातर कथन या कदम उनके होते ही नहीं है। राष्ट्रपति, जो सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते/होती हैं, वे नई चुनी संसद में और हर वर्ष की शुरुआत में दिए जाने वाले भाषण में सरकार का लिखा पढ़ते हैं। उसकी नीतिगत प्राथमिकताओं, समकालीन चुनौतियों के सार और उनसे निजात पाने के उपायों सहित आने वाले वर्ष की योजनाओं का खाका पेश करते/करती है।

संसद का सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर बहस करके उसे देश की आम राय बनाता है या बनाने का प्रयास करता है।

इस बार के अभिभाषण पर पहला अनूठा काम तो यह हुआ कि नेता प्रतिपक्ष दृ जो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है दृ को बोलने ही नहीं दिया गया। नेता सत्तापक्ष लोकसभा में बोलने से ही कतरा गया। बहस पर प्रधानमंत्री का जवाब असहमतियों का संज्ञान, आशंकाओं का समाधान और संकल्पों का पुनराख्यान होता है। भले उसे निचला सदन कहा जाता हो, किन्तु लोकसभा ही इसका मुख्य स्थान होती है। यह जानते हुए भी प्रधानमन्त्री मोदी लोकसभा में जवाब देने नहीं आये। लोकसभा अध्यक्ष 'जी' ने बिना उनके बोले ही ध्वनिमत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित घोषित कर दिया।

सिर्फ इतना भर अनोखा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के लोकसभा में न आने की जो वजह अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बताई वह और भी गजब थी। उन्होंने सदन को सूचित किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा और अप्रिय घटना की आशंका के चलते उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में न आने की सलाह दी थी।

उन्होंने दावा किया कि उनके पास 'पुख्ता जानकारी' थी कि विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री के आसन तक पहुँचकर कोई अप्रत्याशित या अनुचित कृत्य कर सकते थे।

उन पर शारीरिक हमला करके संसद की मर्यादा तार–तार करने की 'योजना' थी ।

हालांकि उन्होंने आज तक नहीं बताया कि यह पुख्ता जानकारी क्या थी। यह जरूर कहा कि महिला सांसदों से प्रधानमत्री पर हमला करवाये जाने की 'योजना' थी।

जब मीडिया ने देश के सबसे अधिक सुरक्षित घेरे में रहने वाले प्रधानमत्री मोदी के खुद अपनी ही उतनी ही सुरक्षित संसद में असुरक्षित और कथित हमले की आशंका से घिरे रहने की बात पर आश्चर्य जताते हुए सवाल किये, तो सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के एक नेता दीपक रेड्डी ने कहा और बाद में आई टी सैल सहित पूरे कुनबे ने दो. हराया कि संसद में हथियार नहीं लाये जा सकते, तो क्या हुआ, विपक्ष की महिला सांसद मोदी जी को अपने 'दांतों से तो काट ही सकती थी'!!

इस पूरे त्रासद प्रहसन को देखते हुए अनायास ही दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ "हालाते जिस्म, सूरते जां और भी खराब / चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब / नजरों में आ रहे हैं नज़ारे बहुत बुरे / होंठों पे आ रही है जुबां और भी खराब।" याद आ गयीं। अब लिखा–पढ़ी में तो खराब जुबान इस्तेमाल नहीं की जा सकती, इसलिए नहीं कर रहे हैं दृ मगर मोदी जी ने यह सभ्रांतता नहीं बरती दृ जिस जवाब को देने से बचने के लिए वे लोकसभा से खिसक गए थे, उसे देने के लिए वे सज–धज कर राज्यसभा में पहुंच गए और ऐसा बमके कि बकौल ओम बिडला लोकसभा की भले बचा ली गयी हो, राज्य सभा की गरिमा पूरी तरह से तार–तार कर के रख दी ।

राज्यसभा का उनका भाषण भाषा और आत्मश्लाघा दृ जिनमें पहले के उल्लंघन और दूसरे के आलिंगन दोनों में वे पहले से ही सारी सीमाएं लांघ–उलांघ चुके हैं दृ की नकारात्मकता की नयी सीमा रेखा ही तय कर दी। अभी तक जो बातें वे अपने निशिकांत दुबों, गिरिराज सिंहों और अनुराग ठाकुरों जैसे सांसदों को ष्छूः बोलकर बुलवाया करते थे, लगभग वे ही सब दृ ज्यादातर आधारहीन बातें दृ स्वयं प्रधानमन्त्री ने अपने उग्र लहजे में बोलीं। बोलते–बोलते वे अपने से पहले के सभी प्रधानमंत्रियों को खारिज करते हुए बोले कि 'पहले वालों के पास ना कोई सोच थी, ना उनके पास कोई विजन था और ना ही कोई इच्छाशक्ति थी।श इस तरह उन्होंने अपनी आदत के अनुरूप ही खुदी को इतना बुलंद कर लिया कि खुद ही खुदा हो गए। इस खुदाई में उन्हें अपने लिए कब्र खुदने के नारे भी सुनाई दे गए।

दो–ढाई किलो रोज की गालियाँ भी खाने को मिलती नजर आ गयीं। इसके जो कारण उन्होंने गिनाये, जो उदाहरण उन्होंने चुने, वे सब के सब विभाजनकारी, ध्रुवीकरण वाले थे। सौ साल के हुए संघ के एजेंडे वाले थे।

इसमें भी वे थोड़े से और आगे बढ़े और एक दलबदलू सांसद पर की गयी छींटाकशी को भी इसके साथ जोड़कर इसे सिखों का अपमान, यहाँ तक कि गुरुओं तक का अपमान बता दिया। ध्यान रहे यह बात वे सज्जन कह रहे थे, जिनके पूरे कुनबे का आजादी के महासंग्राम के साथ गद्दारी का भरा–पूरा कलुषित इतिहास है।

इसके बावजूद भी जो दिन रात खुद को छोड़ बाकी सबको गद्दार कहते–कहते कोहराम मचाये रहते हैं, वे एक पालाबदल सांसद पर की गयी टिप्पणी को सिख धर्म और उसके गुरुओं का अपमान बताकर खेल खेल रहे थे। लगता है, उन्होंने अमरीकी पत्रिका टाइम मैगज़ीन द्वारा 2019 में दिए श्डिवाइडर इन चीफश के तमगे को संसद के मंच पर भी प्रमाणित करने की ठान ली थी।

अपने 5 फरवरी 2026 को राज्य सभा में दिए 97 मिनट दृ एक घंटा 37 मिनट –– के इस भाषण में नाम–उपनाम चुराने, घुसपैठ, सार्वजनिक उद्योगों में किये गए कथित रिफॉर्म्स, गंदे पानी से बच्चों की मौतों की भयावह खबरों के बीच बच्चों की जान बचाने के खोखले दावों के पुलिंदों आदि–इत्यादि सहित आरएसएस की शाखाओं में फैलाई जाने वाली अफवाहों, बोले जाने वाले असत्यों और अर्धसत्यों को देश की संसद की कार्यवाही का ही हिस्सा बना दिया, ताकि आने वाले वर्षों में इनकी प्रामाणिकता के स्रोत के रूप में राज्यसभा की कार्यवाही से दृष्टांत दिए जा सकें।

अपने इस भाषण में प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा के फर्क को स्पष्ट करते हुए एक जगह कहा था कि 'यह उच्च सदन है, यहाँ भाषणों का स्तर ऊंचा होता है।श मगर अपने इसी भाषण की भाषा, लहजे और तरीके से उन्होंने बता दिया कि वे इस फर्क की कितनी परवाह करते हैं। जितने दावे उन्होंने किये, उनकी वास्तविकता वे स्वयं जानते थे, इसलिए एक भी दावे की पुष्टि में कोई तथ्य या आंकड़ा देने की जोखिम उन्होंने नहीं उठाई। विश्व का भारत के प्रति बढ़ता आकर्षण, उसका वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन जाना, विश्व के साथ स्पर्धा के लिए पूरी तरह तैयार होना, विश्व में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उनका समाधान देने के लिए न सिर्फ आशा की एक किरण बन जाना, बल्कि समाधान देना भी, 'मेजर इकोनॉमी में भारत का ग्रोथ बहुत हाई होना' और अर्थव्यवस्था का मजबूत होना वगैरा के दावों की जन्नत की हकीकत उन्हें पता थी, लेकिन मन के बहलाने को ये ख्याल अच्छा बताने का मुगालता खुद भी पाल रहे थे और भक्तों को भी पलवा रहे थे।

ऐसा ही होता है, जब देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर कहने–सुनने से मुंह चुराना हो, तो बे सिर–पैर की बातें बनाने की पतली गली ही सूझती हैं। शायद वे भूल रहे हैं कि अब दुनिया डिजिटल हो चुकी है। अब कोई कोना, किनारा ऐसा नहीं बचा है, जहां छुपा जा सके। सेवानिवृत्त थल सेनाध्यक्ष नरवाणे की वह किताब, जिसे उनकी सरकार अब तक अप्रकाशित बता रही थी, छपकर आ चुकी थी और मोदी और उनकी सरकार की निर्णय अनिश्चितता की पोल खोल चुकी थी। इस पर देश को जवाब देने से बचना था। मोदी जी के माय डिअर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प के डिअरेस्ट फ्रेंड और इतिहास के सबसे घिनौने दलाल जेफरी एपस्टीन की जुगुप्सा जगाने वाली फाइलों का प्रेत दुनिया के सर पर नंगा नाच कर रहा है और इतने गंदे आदमी के साथ नजदीकी रिश्ता रखने वाला. ` में मोदी और उनकी सरकार, दरबारी पूँजीवाद के हुकुम और दरबार –– सभी के नाम सरे बाजार आम हो रहे थे। भारत के अलावा एपस्टीन नरक में नामजद पाए जाने वालों के दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे थे रू उस पर चर्चा से बचना था । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बनी विश्व व्यवस्था में स्वयं मोदी की हांकी डींग में "एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रही है।

और पूरी दुनिया का झुकाव भारत की तरफ है" की बजाय भारत झुकता, शरणागत होता दिख रहा है, इसे छुपाना था रू इसलिए गाल बजाना ही बजाना था ।

पूरा भाषण इसी तरह की गालबजाऊ लफ्फाजियों से भरा हुआ था। ढीठपन की पराकाष्ठा यह थी कि 27 देशों वाली यूरोपीयन यूनियन के साथ हुए व्यापार समझौते को सारे समझौतों की अम्मा दृ मदर ऑफ़ ऑल डील्स दृ बताते हुए मोदी अमरीका के साथ हुए आत्मसमर्पण की पाँ पाँ ट्रेड डील दृ फादर ऑफ़ ऑल सरेंडर्स – वाले शर्मनाक करार को ऐसा व्यापार समझौता बता रहे थे, जिसकी खुद उनके मुताबिक़ 'अक्खा वर्ल्ड खुलकर तारीफ़ कर रहा है'।

हालांकि इसे करार कहने की बजाय ट्रम्प डिक्टेट कहना ज्यादा सही होगा।

वही डिक्टेट, जिसकी समर्पणकारी शर्तों के बारे में पूछने पर वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि विदेश मंत्री से पूछिए रू विदेश मंत्री कहते हैं कि वाणिज्य मंत्री से पूछिए।

मोदी ने भी यही कुलधर्म निबाहा और बजाय इस सर्मपण करने वाले, ट्रम्प द्वारा थोपे गए अपमान. जनक समझौते की खूबियाँ बताने के उनने भी पीयूष गोयल के सर पर ही ठीकरा फोड़ दिया। कह दिया कि वे पहले बता ही चुके हैं।

इस समझौते की किस अक्खा वर्ल्ड में तारीफ़ हो रही है, यह तो दिवास्वप्न टूटने के बाद ही मोदी बताएँगे या मुमकिन है कि न भी बताएं। मगर ट्रम्प ने इसके जरिये पूरी दुनिया में भारत की जो कमजोर, असहाय और ट्रम्प के आज्ञाकारी अधीनस्थ की छवि बनाई है, वह सचमुच में लानत की बात है ।

सरेंडर के समानार्थी हो चुके नरेंदर की अगुआई वाली यह डील देश की कृषि, उद्योग, वाणिज्य, अर्थव्यवस्था के लिए कितनी घातक है, इस बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है। यहाँ उसे दोहराने की बजाय ट्रम्प द्वारा "मैं मोदी का राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर सकता हूँ, मगर नहीं करूंगा, क्योंकि मोदी मुझे प्यार करता है" जैसी फूहड़ और मातहतों के लिए उनके आकाओं द्वारा बरती जाने वाली भाषा बार–बार बोलकर दुनिया भर में भारत का जो मजाक उड़ाया है, वह स्तब्ध कर देने वाला है। उससे भी ज्यादा चौंकाने और चिंतित कर देने वाली है इस ब्लैकमैलिंग पर मोदी सरकार की चुप्पी दृ जिसकी गूँज–अनुगूंज का असर आने वाले वर्षों में मातहती के और नुकीला होने, दुनिया के बदतरीन साम्राज्यवादी देश के धृतराष्ट्र आलिंगन में और बुरी तरह जकड़ने के रूप में सामने आयेगा। इस कथित डील ने भारत की संप्रभुता को ही खतरे में डाल दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश से अपने हितों के अनुरूप फैसले लेने की स्वतन्त्रता ही नहीं छीनी, उसके व्यापार–कारोबार पर खुल्लमखुल्ला पहरेदारी भी बैठा दी है । जिसे शानदार डील बताने का झुनझुना बजाते हुए संघी बटुक भक्त आकाश पाताल एक किये हुए हैं, इसमें बाकायदा आदेश जारी करके ट्रम्प ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निगरानी करने के लिए अपने तीन वरिष्ठ मंत्रियों की तैनाती की है। ट्रंप द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के अनुसार, भारत द्वारा रूसी तेल के आयात पर नजर रखने दृ मोनिटरिंग –– के लिए मुख्य रूप से तीन अमरीकी मंत्रियों दृ अमरीका में मंत्रियों को सेक्रेट्री कहा जाता है –– को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के समकक्ष अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक इस निगरानी दल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के समकक्ष अमरीका के विदेश सचिव मार्को रुबियो और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समकक्ष अमरीकी ट्रेज़री सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट इसके सदस्य होंगे। जाहिर है, ट्रम्प ने किसी छोटे–मोटे को नहीं, अपने सर्वोच्च मंत्रियों को इस काम पर लगाया है। इस लज्जित कर देने वाली निगरानी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत ष्प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षष् रूप से रूस से तेल का आयात फिर से शुरू न करे। यदि ये अधिक. ारी पाते हैं कि भारत ने रूसी तेल खरीदना फिर से शुरू कर दिया है, तो वे ट्रंप को भारत पर फिर से 25ः दंडात्मक टैरिफ लगाने की सिफारिश करेंगे। इसी के साथ वाणिज्य सचिव को इस काम के लिए अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ समन्वय करने का अधिकार भी दिया गया है।

यह एक स्वतंत्र और संप्रभु देश को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी शर्त है, जिसे 8–10 हजार सैनिकों वाला भूटान या छोटी–सी सैन्य शक्ति वाला नेपाल भी मंजूर नहीं करता। उनकी बात तो दूर रही, बिना सेना वाला कोई टापू देश भी कभी स्वीकार नहीं करता।

मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतना अपमानजनक और देशहित विरुद्ध समर्पण उसने किस मजबूरी में किया? ऐसा करने का अधिकार उसे किसने दिया?

इन्हीं सब अपराधों को छुपाना है, इसलिए राज्यसभा में तेवरों के स्वांग दिखाए जा रहे हैं, हिन्दू सम्मेलनों के भंडारे गाँव–गाँव किये जा रहे हैं और इस या उस बहाने तनाव और उन्माद खड़े किये जा रहे हैं।

ऐसे में जनता तक सही जानकारी पहुँचाना ही बचाव है, जनता का एकजुट संघर्ष ही एकमात्र हथियार है।

(लेखक श्लोकजतनश के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। संपर्क रू 94250–06716)

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

डाक विभाग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारतीय डाक के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

सबका जम्मू कश्मीर

सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग (डीओपी) ने आज भारत के अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारतीय डाक के व्यापक डाक नेटवर्क के माध्यम से म्यूचुअल फंड उत्पादों का वितरण को संभव बनाना है। डाक विभाग, देशभर में फैले अपने 1.64 लाख से अधिक डाकघरों के विशाल नेटवर्क का उपयोग करते हुए, एनएसई के साथ मिलकर काम करेगा। एनएसई के पास म्यूचुअल फंड लेनदेन को संभालने के लिए एक मजबूत ऑनलाइन प्रणाली है। यह प्रणाली ऑर्डर देने से लेकर निपटान तक सभी प्रक्रियाओं को कवर करती है और एसईबी के नियमों का पालन करती है। इस सहयोग का उद्देश्य सभी के लिए म्यूचुअल फंड उत्पादों की पहुंच को, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में, काफी हद तक बढ़ाना है। यह रणनीतिक साझेदारी सरकार के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप है, इसमें भारतीय डाक के भरोसे, सुलभता और व्यापक पहुंच को राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) के बाजार बुनियादी ढांचे और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ जोड़ा गया है। इस पहल से निवेशकों में पूंजी बाजार से जुड़े वित्तीय उत्पादों के प्रति जागरूकता, पारदर्शिता और भागीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। डाक विभाग की महाप्रबंधक (नागरिक केंद्रित सेवाएं और ग्रामीण व्यवसाय) सुश्री मनीषा बंसल बादल और एनएसई के मुख्य व्यापार विकास अधिकारी श्री श्रीराम कृष्णन ने नई दिल्ली में डाक विभाग और एनएसई के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत, डाक विभाग के चयनित कर्मचारियों की पहचान की जाएगी, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रमाणित म्यूचुअल फंड वितरक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी एनआईएसएम प्रमाणन और ईयूआईएन पंजीकरण सहित अनिवार्य प्रमाणन और नियामक अनुपालन के अधीन एनएसई के म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के माध्यम से म्यूचुअल फंड उत्पाद और संबंधित निवेशक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा और आपसी सहमति से नवीनीकरण का प्रावधान भी है।

इस अवसर पर डाक विभाग की महाप्रबंधक (सीसीएस और आरबी) सुश्री मनीषा बंसल बादल ने कहा, "डाक विभाग ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और नागरिक–केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनएसई के साथ यह साझेदारी भारतीय डाक को अपने ग्राहक. ों को आधुनिक निवेश समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाएगी, साथ ही निवेशक संरक्षण, पारदर्शिता और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखेगी।"

जम्मू के लिए दीर्घकालिक जल सुरक्षा की जरूरत : सिंधु जल संधि के निलंबन को अवसर में बदलना चाहती है सरकार

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू क्षेत्र में लगातार गहराते जल संकट को लेकर सरकार ने दीर्घकालिक और दूरदर्शी योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जम्मू की बढ़ती आबादी, बदलते जलवायु हालात और सीमित होते पारंपरिक जल स्रोतों को देखते हुए अब तात्कालिक समाधान पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के वर्तमान निलंबन की स्थिति का पूरा लाभ उठाकर जम्मू क्षेत्र में प्रमुख और स्थायी जल अवसं. रचना परियोजनाओं को लागू करना चाहती है, ताकि आने वाले दशक. ों तक जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री यह बात जम्मू और कश्मीर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कही। इस दौरान भाजपा के कई विधायकों, जिनमें शाम लाल शर्मा प्रमुख थे, ने जम्मू में जल संकट और सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए। विधायकों ने चिंता जताई कि जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में गर्मियों के दौरान पानी की भारी किल्लत होती है और कई क्षेत्रों में लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि समस्या गंभीर है और सरकार इसे हल्के में नहीं ले रही है।

उमर अब्दुल्ला ने सदन को बताया कि सरकार ने निष्क्रिय पड़े ट्यूबवेलों, पुराने जल स्रोतों और अन्य वैकल्पिक साधनों को पुनर्जीवित करने के प्रयास शुरू किए हैं। कई स्थानों पर पुराने ट्यूबवेल दोबारा चालू किए जा रहे हैं और भूजल स्तर का आकलन कर नए स्रोत तलाशे जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि ये सभी कदम केवल अस्थायी राहत देने वाले हैं। इनसे कुछ समय के लिए पानी की समस्या को कम किया जा सकता है, लेकिन ये जम्मू की दीर्घकालिक जल जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं।

जर्मनी में आयोजित बायोफैच 2026 में भारत 'कंट्री ऑफ द इयर' नामित

सबका जम्मू कश्मीर

जैविक उत्पादों के लिए विश्व के अग्रणी व्यापार मेले बायोफैच 2026 में भारत को 'कंट्री ऑफ द इयर' नामित किया गया है। इसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2026 तक जर्मनी के नूरेमबर्ग में किया जा रहा है।

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) बायोफैच 2026 में भारत की प्रमुख और प्रभावशाली भागीदारी का आयोजन कर रहा है। इसमें भारत की भागीदारी देश की समृद्ध कृषि विरासत और जैविक उत्पादों के प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में इसकी मजबूत क्षमता को दर्शाएगी। जर्मनी में आयोजित बायोफैच जैविक खाद्य पदार्थों और कृषि को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनी है। एपीडा एक दशक से अधिक समय से बायोफैच में भाग ले रहा है और इसमें लगातार अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है।

बायोफैच 2026 में भारत की भागीदारी पिछले संस्करणों की तुलना में इस बार महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाती है जो भारतीय जैविक निर्यात के बढ़ते प्रभाव, जैविक उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग और निर्यातकों, संघों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की बढ़ती हिस्सेदारी को प्रतिबिंबित करती है। 14 वर्षों के अंतराल के बाद भारत का जैविक कृषि क्षेत्र एक बार फिर बायोफैच 2026 में केंद्र बिंदु बनने के लिए तैयार है।

बायोफैच 2026 में एपीडा की ओर से बनाया गया भारत का राष्ट्रीय मंडप 1,074 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा और इसमें जैविक उत्पादों के निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, जैविक प्रयोगशालाओं, राज्य सरकारी संगठनों और कमोडिटी बोर्ड सहित 67 सह–प्रदर्शक शामिल होंगे। भारतीय मंडप में चावल, तिलहन, जड़ी–बूटियां, मसाले, दालें, काजू, अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, दालचीनी, आम की प्यूरी और आवश्यक तेलों सहित विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा।

भारत के मंडप में 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शक भाग ले रहे हैं जो देश की व्यापक कृषि और क्षेत्रीय विविधता को दर्शाते हैं।

इनमें असम, मेघालय, मणिपुर, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और उत्तराखंड शामिल हैं। यह भागीदारी अलग–अलग क्षेत्रों के विशिष्ट जैविक उत्पादों और मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों को दर्शाने के साथ अंतरराष्ट्रीय जैविक व्यापार में भारत की वार्षिक वृद्धि को प्रदर्शित करती है।

भारतीय मंडप में उत्पादों के प्रदर्शन के अति. रिक्त आगंतुकों को भारतीय जैविक उत्पादों के स्वाद और सुगंध को प्रदर्शित करने वाले विशेष खाद्य पदार्थों को चखने का अवसर भी मिलेगा। इस दौरान प्रीमियम जैविक बासमती चावल और मसालों से तैयार की गई ताजा सुगंधित बिरयानी के नमूने की भी प्रस्तुति की जाएगी।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् 68वीं राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 2026 का आयोजन करेगी, जिसमें एमएसएमई के लिए क्लस्टर–आधारित विकास पर मुख्य जोर

सबका जम्मू कश्मीर

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एनपीसी) 12 फरवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाएगी और 12 से 18 फरवरी 2026 तक पूरे देश में राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का आयोजन करेगी। 68वीं राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का विषय है "क्लस्टर विकास इंजन के रूप मेंरू एमएसएमई उत्पादकता को अधिकतम बनाना"।

यह विषय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अध्यक्ष श्री पीयूष गोयल के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मजबूत करने, विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने पर जोर के अनुरूप है।

भारत के हालिया व्यापार समझौतों के पृष्ठभूमि में, क्लस्टर–आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करना उत्पादकता को तेज करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने, सतत औद्योगिक विस्तार को प्रेरित करने तथा भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक साधन के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। देशभर में एनपीसी के 12 क्षेत्रीय निदेशालयोंकृबेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गांधीनागर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई और पटनाकृके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। देश भर में स्थित 21 स्थानीय उत्पादकता परिषद्, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय, राज्य सरकारें, उद्योग संघ तथा शैक्षणिक संस्थान सप्ताह के दौरान जागरूकता और प्रसार गतिविधियों के संचालन में सहयोग करेंगे।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त समाज है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका दृष्टिकोण उत्पादकता में एक ज्ञान नेता बनना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने में सहायता प्रदान करना है और इसके अलावा सतत एवं समावेशी सामा. जिक–आर्थिक विकास में योगदान देना है। एनपीसी सरकार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संगठनों को औद्योगिक इंजीनियरिंग, पर्यावरण एवं ऊर्जा प्रबंधन, कृषि–व्यवसाय, आर्थिक सेवाएं, गुणवत्ता प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन आदि क्षेत्रों में परामर्श तथा प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करती है। एनपीसी उत्पादकता पर शोध भी करती है तथा टोक्यो–आधारित एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ) का यह सदस्य भी है, जो एक अंतर–सरकारी निकाय है जिसमें भारत सरकार संस्थापक सदस्य एवं वर्तमान अध्यक्ष भी है।

सरकार ने पूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवा और पद संबंधी पुनर्रोजगार) संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया

सबका जम्मू कश्मीर

केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत पूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवा और पदों संबंधी पुनर्रोजगार) संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है। प्रमुख परिवर्तन नियम 2 (सी) (प) को संशोधित करता है, जिसमें भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना के साथ–साथ सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) में किसी भी रैंक में, चाहे योद्धा हों या गैर–यौद्धा, सेवा दे चुके कर्मियों को केंद्रीय सिविल सेवाओं में पूर्व सैनिकों के पुनर्रोजगार के लिए परिभाषा के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

इस कदम से उस पहले वाली अस्पष्टता को दूर कर दिया गया है कि क्या एमएनएस अधिकारी, जो कि कमीशन प्राप्त अधिकारी होते हैं, अन्य पूर्व सैनिकों के समान पुनर्रोजगार लाभों के हकदार थे या नहीं। यह संशोधन पुनर्रोजगार नियमों के तहत एमएनएस कर्मियों को औपचारिक रूप से मान्यता देता है और पूर्व रक्षा कर्मियों के एक व्यापक वर्ग के लिए पुनर्वास और दूसरे करियर के अवसरों को मजबूती प्रदान करता है।

नियम 2, खंड (सी) संशोधन के तहत श्पूर्व सैनिकश की परिभाषा में अब नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ श्भारतीय संघ की सैन्य नर्सिंग सेवाश भी स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है। यह नियम उन सभी पर लागू होता है जिन्होंने किसी भी रैंक पर, चाहे योद्धा के रूप के या गैर–योद्धा के रूप में सेवा कीं हों। यह संशोधन 9 फरवरी, 2026 को इसके प्रकाशन के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह संशोधन औपचारिक रूप से एमएनएस कर्मियों को निम्नलिखित लाभों तक पहुंच प्रदान करता हैरू

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर
संपादकीय

डीपफेक का धोखा और डिजिटल सख्त नियमों की अनिवार्यता

वैश्विक परिदृश्य भी इसी संकट की ओर संकेत करता है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग की न्यूनतम आयु निर्धारित करने जैसे कदम उठाए हैं। अमेरिका में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभावों की जांच के लिए ऐतिहासिक मुकदमे चल रहे हैं।

वंदे मातरम् विमर्श

संपादक – राज कुमार

बंगाल में वंदे मातरम् केवल एक नारा या औपचारिक गीत नहीं है। यह साहित्यिक विरासत है, जो बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की कल्पना से जन्मी और एक ऐसे दौर में सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनी, जब कविता स्वयं राजनीति का रूप ले रही थी। इसे केवल प्रशासनिक आदेश या समकालीन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का औजार मान लेना उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आयामों को सीमित कर देना है। वंदे मातरम् का जीवन उस जटिल संगम में है जहाँ संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रबोध एक–दूसरे से संवाद करते हैं। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम् को किसी सरकारी अधिसूचना के रूप में नहीं लिखा था। उन्होंने इसे उस समय की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय जागरण की भावना से ओतप्रोत साहित्यिक रचना के रूप में गढ़ा। उनके लिए यह मातृभूमि के प्रति भावनात्मक समर्पण की अभिव्यक्ति थी, जिसमें आध्यात्मिकता, सौंदर्य और राष्ट्रप्रेम का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाई देता है। समय के साथ यह गीत औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसने लाखों लोगा. ` को प्रेरित किया और एक साझा भावना का माध्यम बना। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसके स्वरूप और उपयोग को लेकर जो निर्णय लिए गए, वे भावनात्मक आवेग से नहीं, बल्कि राजनीतिक विवेक से प्रेरित थे। स्वतंत्र भारत के निर्माताओं के सामने एक अत्यंत जटिल परिस्थिति थी। विभाजन के घाव ताजा थे, समाज में असुरक्षा और अविश्वास का वातावरण था, और एक बहुलतावादी राष्ट्र को स्थिरता प्रदान करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। ऐसे समय में राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक था। वंदे मातरम् को जिस रूप में सार्वजनिक जीवन में स्थान मिला, वह किसी अस्वीकृति का परिणाम नहीं था, बल्कि उस व्यापक सहमति का हिस्सा था जो विविधता में एकता को सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई थी। यह समझ थी कि राष्ट्रीय प्रतीक तभी टिकाऊ होते हैं जब वे साझा किए जा सकें, थोपे न जाएँ। आज जब उस ऐतिहासिक सहमति को फिर से प्रश्नांकित करने की कोशिश होती है, तब यह विचार करना जरूरी है कि हम इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं या उसे अपने वर्तमान राजनीतिक आग्रहों के अनुसार सरल बनाना चाहते हैं। इतिहास केवल गौरव का संग्रहालय नहीं है, जिसे मनचाहे ढंग से सजाया जा सके। वह समझौतों, मतभेदों और विवेकपूर्ण निर्णयों का दस्तावेज है। उन निर्णयों को त्रुटि कहकर खारिज कर देना उस लोकतांत्रिक संवेदनशीलता की अवहेलना है, जिसने भारत को एकजुट रखा। बंगाल के दृष्टिकोण से यह विमर्श और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। बंकिमचंद्र की विरासत किसी कठोर विचारधारा की नहीं, बल्कि बौद्धिक जटिलता और सांस्कृतिक संवाद की रही है। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता, आस्था और राष्ट्रवाद, साहित्य और राजनीति के बीच सेतु का निर्माण किया। वंदे मातरम् उसी बहुआयामी सोच की उपज है। इसे एकमात्र, राज्य–निर्धारित अर्थ में सीमित करना उस रचनात्मक ऊर्जा के साथ अन्याय होगा, जिसने इसे जन्म दिया। राष्ट्रीय प्रतीकों की शक्ति उनकी समावेशिता में निहित होती है। वे पहले जोड़ते हैं, फिर प्रेरित करते हैं। जब उन्हें रोजमर्रा की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बना दिया जाता है, तो उनकी नैतिक आभा कम हो जाती है। वे साझा पहचान के बजाय विभाजन के चिह्न बन सकते हैं। वंदे मातरम् की दीर्घायु का कारण यह है कि उसने अलग–अलग भारतीयों के लिए अलग–अलग अर्थ ग्रहण किए, फिर भी अपनी मूल पहचान बनाए रखी। यही लचीला. पन उसकी वास्तविक शक्ति है। राष्ट्र के प्रति सम्मान का अर्थ यह नहीं कि हर प्रतीक को कठोर अनुशासन का विषय बना दिया जाए। सच्चा सम्मान उस व्यापक, खुली जगह को सुरक्षित रखने में है जहाँ लोग अपनी समझ और संवेदना के अनुसार उससे जुड़ सकें। बंकिमचंद्र को श्रद्धांजलि देने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि उनके गीत को जीवंत, बहस योग्य और बहुव्याख्यात्मक बनाए रखा जाए। जब वंदे मातरम् को स्मरण किया जाए, तो वह स्वाभाविक श्रद्धा से हो, न कि अनिवार्यता के दबाव से। यही दृष्टि एक परिपक्व और बहुल लोकतंत्र की पहचान है।

ललित गर्ग

डिजिटल युग में सूचना की गति जितनी तीव्र हुई है, उतनी ही तेजी से भ्रम, छल और दुष्प्रचार की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक तकनीक ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। अब केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि चेहरों, आवाज़ों और हाव–भाव के जरिए भी झूठ को सच की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने डीपफेक और एआई जनित सामग्री के नियमन के लिए आईटी नियमों को और सख्त करने का निर्णय लिया है। 20 फरवरी से लागू होने जा रहे नए प्रावधानों के अनुसार एआई द्वारा निर्मित सामग्री पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा और किसी भी अवैध या भ्रामक सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना या ब्लॉक करना होगा। पहले यह समयसीमा 36 घंटे थी। यह परिवर्तन केवल तकनीकी संशोधन नहीं, बल्कि डिजिटल नैतिकता और लोकतांत्रिक जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है।

पिछले कुछ वर्षों में डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग भयावह रूप से सामने आया है। राजनीतिक नेताओं के फर्जी वीडियो, अभिनेत्रियों की अश्लील रूप से परिवर्तित तस्वीरें, सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले ऑडियो क्लिप और आर्थिक धोखाधड़ी के लिए तैयार किए गए कृत्रिम संदेशकृये सभी उदाहरण बताते हैं कि तकनीक स्वयं तटस्थ नहीं रहती; उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों संभव हैं। जब सत्य को तोड़ा–मरोड़ा जा रहा हो और झूठ को परिष्कृत तकनीक की सहायता से प्रमाणिकता का आवरण पहनाकर प्रस्तुत किया जा रहा हो, तब समाज में अविश्वास का वातावरण बनना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा नियमन की पहल आवश्यक प्रतीत होती है, क्योंकि यह केवल अभिव्यक्ति का प्रश्न नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की प्रतिष्ठा से जुड़ा विषय है।

नए नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से बढ़ाई गई है। अब उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता को यह जानकारी मिले कि साझा की जा रही सामग्री एआई से निर्मित है या नहीं। इससे पारदर्शिता का एक न्यूनतम मानक स्थापित होगा। साथ ही, तीन घंटे की समयसीमा यह संकेत देती है कि सरकार डिजिटल अपराधों की गंभीरता को समझ रही है। डीपफेक वीडियो के वायरल हो जाने के बाद उसका खंडन अक्सर प्रभावहीन हो जाता है, इसलिए त्वरित कार्रवाई ही नुकसान को सीमित कर सकती है। हालांकि, यह भी सच है कि इतनी कम समय सीमा में सामग्री की सत्यता की जांच करना तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत जटिल कार्य है। इससे प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी तंत्र को अत्यधिक सुदृढ़ करना पड़ेगा, जो लागत और संचालन दोनों स्तरों पर चुनौतीपूर्ण होगा।

यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि "आपत्तिजनक" या "भ्रामक" सामग्री की परिभाषा कौन और किस आधार पर तय करेगा। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। यदि नियमन की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत नहीं होगी, तो इसके दुरुपयोग की आशंकाएँ जन्म लेंगी। अतीत में भी जब–जब सोशल मीडिया पर नियंत्रण के प्रयास हुए, तब कुछ वर्गों ने इसे सरकारी अतिक्रमण के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए नियमन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमों का प्रयोग असहमति को दबाने के लिए नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से दुष्प्रचार और अपराध को रोकने के लिए हो। इस दिशा में स्वतंत्र निगरानी तंत्र, न्यायिक समीक्षा और पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य घटक हो सकते हैं।

वैश्विक परिदृश्य भी इसी संकट की ओर संकेत करता है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग की न्यूनतम आयु निर्धारित करने जैसे कदम उठाए हैं। अमेरिका में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभावों की जांच के लिए ऐतिहासिक मुकदमे चल रहे हैं। वहां की बड़ी तकनीकी कंपनियों पर युवाओं को लत लगाने वाली संरचनाएं विकसित करने के आरोप लगे हैं। विशेषज्ञों का मत है कि कई युवा जब अपने फोन से दूर किए जाते हैं तो वे मनोवैज्ञानिक ही नहीं, शारीरिक असहजता भी अनुभव करते हैं। यह स्थिति केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं है; भारत सहित विकासशील देशों में भी सोशल मीडिया का अनियंत्रित विस्तार सामाजिक और मानसिक संकट का कारण बन रहा है।

एआई उद्योग स्वयं भी एक नैतिक दुविधा के दौर से गुजर रहा है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में कंपनियां तकनीकी श्रेष्ठता की दौड़ में लगी हैं। इस दौड़ में सुरक्षा और नैतिकता के प्रश्न अक्सर पीछे छूट जाते हैं। हाल ही में एक प्रमुख कंपनी के सुरक्षा शोधकर्ता द्वारा विवादास्पद परियोजनाओं की अनियंत्रित गति पर असहमति जताते हुए त्यागपत्र देना इस तनाव का संकेत है। तकनीक की प्रगति जितनी तेज होगी, नियामक ढांचे उतनी ही तेजी से अप्रासंगिक होते जाएंगे यदि उन्हें समयानुकूल अद्यतन न किया जाए। इसलिए नियमन को केवल दंडात्मक नहीं बल्कि दूरदर्शी और सहभागी होना चाहिए।

भारत के संदर्भ में यह विषय और भी संवेदनशील है। यहां डिजिटल क्रांति ने अभूतपूर्व विस्तार पाया है। करोड़ों नए उपयोगकर्ता हर वर्ष ऑनलाइन आ रहे हैं। ऐसे में यदि असली और नकली के बीच का फर्क स्पष्ट न रहे, तो लोकतांत्रिक विमर्श ही संदिग्ध हो जाएगा। चुनावी प्रक्रिया, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक लेन–देन और व्यक्तिगत प्रतिष्ठाकृसभी पर डीपफेक का खतरा मंडरा सकता है। इसलिए एआई जनित सामग्री पर लेबलिंग का प्रावधान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सूचना साक्षरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। परंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि लेबलिंग तभी प्रभावी होगी जब आम उपयोगकर्ता डिजिटल साक्षर हो। अन्यथा वह लेबल को समझे बिना ही सामग्री साझा करता रहेगा।

डिजिटल साक्षरता इस पूरी बहस का केंद्रीय तत्व है। कानून और नियम आवश्यक हैं, लेकिन नागरिकों की जागरूकता के बिना वे अधूरे रहेंगे। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मीडिया साक्षरता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। लोगों को यह समझना होगा कि हर वीडियो, हर ऑडियो और हर संदेश पर आंख मूंदकर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। तथ्य जांच की आदत, स्रोत की जांच और आलोचनात्मक सोच आज के समय में उतनी ही आवश्यक है जितनी पढ़ना–लिखना।

आगामी ई–समिट और भारत के 'इंडिया एआई मिशन' के संदर्भ में यह और भी प्रासंगिक हो जाता है कि तकनीक का विकास पारदर्शिता, शुद्धता और प्रमाणिकता के मूल्यों के साथ हो। यदि भारत वैश्विक एआई नेतृत्व का दावा करना चाहता है, तो उसे नैतिक मानकों की स्थापना में भी अग्रणी भूमिका निभानी होगी। केवल स्टार्टअप्स और नवाचार की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं; यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि एआई मानव गरिमा, गोपनीयता और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करे। नियमन का उद्देश्य तकनीकी प्रगति को रोकना नहीं बल्कि उसे उत्तरदायी बनाना होना चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण पहलू डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का है।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

पाकिस्तान विवाद के इस सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए आईसीसी को धन्यवाद : राजीव शुक्ला

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच के बहिष्कार को वापस लेने के लिए राजी करने में एक बहुत अच्छा समाधान निकाला है।

बांग्लादेश और श्रीलंका के आग्रह पर पाकिस्तान सरकार द्वारा बहिष्कार का आह्वान वापस लेने के बाद, कोलंबो में 15 फरवरी को होने वाला भारत–पाकिस्तान का बहुचर्चित मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। शुक्ला ने पत्रकारों से कहा, "मैं बीसीसीआई की ओर से आईसीसी अध्यक्ष (जय शाह) और उसके पदाधिकारियों को एक बहुत अच्छा समाधान निकालने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ चर्चा के बाद और सभी पक्षों की बात सुनने के बाद यह निर्णय लिया गया है।"

"यह फैसला क्रिकेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिकेट जारी रहना चाहिए और अब विश्व कप एक बड़ी सफलता होगी। आईसीसी के लिहाज से यह एक बड़ी उपलब्धि है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी की प्रशंसा की है, इसलिए उसने सभी पक्षों की बात सुनी और सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।

अंततः क्रिकेट सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है," अनुभवी प्रशासक और कांग्रेस नेता ने आगे कहा।

यह स्पष्ट था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख अमीनुल इस्लाम द्वारा ढाका में एक बयान जारी कर खेल की भलाई के लिए देश से मैदान में उतरने का आग्रह करने के बाद पाकिस्तान बहिष्कार वापस ले लेगा।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके का भी फोन आया, जिन्होंने उनसे टीम को मैच खेलने की अनुमति देने का आग्रह किया।

सरकार का बयान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी द्वारा शरीफ को आईसीसी के साथ हुई बातचीत की जानकारी देने के बाद आया।

आईसीसी ने इस मुद्दे पर कुछ रियायतें देते हुए बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया, जिसे सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार करने के बाद विश्व कप से बाहर होना पड़ा था।

पाकिस्तान सरकार का यह फैसला भारत के खिलाफ मैचों का बहिष्कार बांग्लादेश के समर्थन में था, क्योंकि टूर्नामेंट की सूची में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था।

भारत ने सऊदी अरब के रियाद में आयोजित विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 में अपनी स्वदेशी रक्षा सामर्थ्य का प्रदर्शन किया

सबका जम्मू कश्मीर

रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ के नेतृत्व में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 8–9 फरवरी, 2026 को सऊदी अरब के रियाद में आयोजित विश्व रक्षा प्रदर्शनी (डब्ल्यूडीएस) 2026 में भाग लिया। उन्होंने विश्व रक्षा प्रदर्शनी (डब्ल्यूडीएस) के उद्घाटन समारोह में अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ भाग लिया और इसमें पहली बार स्थापित भारतीय मंडप का शुभारंभ किया जिसमें रक्षा क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) और निजी भारतीय कंपनियों की ओर से भारत की विनिर्माण क्षमता का प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने सऊदी अरब सैन्य उद्योग (एसएएमआई) और सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय की प्रदर्शनी भी देखी और उनके नवीनतम स्वदेशी तकनीकी विकास की समीक्षा की।

श्री संजय सेठ ने सऊदी अरब के कार्यकारी मामलों के सहायक रक्षा मंत्री डॉ. खालिद बिन हुसैन अल–बियारी के साथ दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने सऊदी अरब के रक्षा विकास प्राधिकरण (जीएडीडी) के प्रशासक डॉ. फलेह बिन अब्दुल्ला अल–सुलेमान से भी मुलाकात की और इस बात का उल्लेख किया कि भारत वैश्विक निर्यात के केंद्र के रूप में उभर रहा है। रक्षा राज्य मंत्री ने एक साथ मिलकर रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से जीएडीडी के अधिकारियों को भारत के अनुसंधान एवं विकास केंद्रों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया।

श्री संजय सेठ ने सऊदी अरब के सैन्य उद्योग महानिदेशालय (जीएएमआई) के प्रशासक श्री अहमद बिन अब्दुलअज़ीज़ अल–ओहाली से मुलाकात की और रणनीतिक सहयोग के साझा क्षेत्रों तथा दोनों देशों की आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को मजबूत करने के संबंध में चर्चा की। रक्षा राज्य मंत्री ने भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए सैन्य उद्योग महानिदेशालय (जीएएमआई) के नेतृत्व में सऊदी अरब के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा का भी प्रस्ताव रखा। रक्षा राज्य मंत्री ने भारतीय दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र की भारतीय और सऊदी कंपनियों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त रूप से सहयोग के महत्व पर बल दिया और ष्मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्डष् के दृष्टिकोण के अंतर्गत विश्व के सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। रक्षा राज्य मंत्री ने यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में विख्यात सऊदी अरब की जन्मस्थली शदिरियाहश का भी दौरा किया। बाद में, उन्होंने भारतीय दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ओर से महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और डिजिटल साक्षरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला।

व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के अनुसार, अमेरिका और भारत बीटीए को पूरा करने के लिए अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर काम करेंगे

सबका जम्मू कश्मीर

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन : व्हाइट हाउस ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में, अमेरिका और भारत पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से व्यापार पर अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे।

इसमें कहा गया है कि दोनों देश सेवाओं और निवेश, श्रम और सरकारी खरीद सहित शेष मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत जारी रखेंगे।

भारत और अमेरिका द्वारा पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते के ढांचे की संयुक्त घोषणा के कुछ दिनों बाद, व्हाइट हाउस ने श्संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते (अंतरिम समझौते) की घोषणा कीश शीर्षक से एक तथ्य पत्रक जारी किया।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कृषि एवं किसान कल्याण के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा

सबका जम्मू कश्मीर

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि मंत्रालय में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। इस दौरान राज्य में कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों, योजनाओं की प्रगति तथा भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई।

श्री नायडू ने आंध्र प्रदेश के किसानों की आवश्यकताओं, फसल विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, सिंचाई, प्रसंस्करण तथा कृषि–आधारित उद्योगों के विस्तार से जुड़े विषय केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखे। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की प्राथमिकताओं को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि आंध्र प्रदेश की कृषि संबंधी सभी प्रमुख समस्याओं का समाधान त्वरित एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राज्य सरकार के साथ समन्वय बढ़ाकर समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।

मुलाकात के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू तथा ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर पेम्मासानी भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में आंध्र प्रदेश की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले 'विकसित भारत जी राम जी योजना में बजट आवंटित किया, जो एक दूरदर्शी और सकारात्मक पहल है तथा कृषि और ग्रामीण विकास के प्रति उसकी गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

32 चेक दायित्वों के तहत कैशलेस इलाज हेतु एम्स-जनरल इंश्योरेंस काउंसिल समझौता

सबका जम्मू कश्मीर

आयुर्वेद को स्वास्थ्य बीमा इकोसिस्टम की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली ने 10 फरवरी 2026 को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (जीआईसी) के साथ एक साझा मनोनयन समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते के साथ, एआईआईए को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के तहत सभी 32 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की सूची में सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे मरीज़ों को योग्य आयुर्वेद–आधारित सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

समझौता ज्ञापन पर एआईआईए के निदेशक प्रो. (वैद्य) पी. के. प्रजापति और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के निदेशक (स्वास्थ्य) श्री सेगर संपतकुमार ने आयुष हेल्थ इंश्योरेंस पर एक्सपर्ट्स के कोर ग्रुप के चेयरमैन प्रो. बेजोन कुमार मिश्रा की मौजूदगी में औपचारिक रुप से हस्ताक्षर किए।

इस कार्यक्रम में प्रोफेसर (डॉ.) महेश व्यास, डीन (पीएचडी), प्रोफेसर (डॉ.) आर. के. यादव, डीन (पीजी), डॉ. अलका कपूर, निदेशक चिकित्सा सेवाएं (डीएमएस) और एआईआईए के अन्य वरिष्ठ संकाय सदस्य भी शामिल हुए। इस अवसर पर, एआईआईए के निदेशक प्रोफेसर (वैद्य) पी. के. प्रजापति ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ, एआईआईए सामान्य बीमा परिषद से जुड़ी सभी 32 बीमा कंपनियों के तहत कैशलेस उपचार सेवाएं प्रदान करने योग्य हो गया है। उन्होंने आयुष मंत्रालय और पूरी एआईआईए टीम के निरंतर प्रयासों के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि इस पहल से आयुर्वेद–आधारित स्वास्थ्य सेवा में पहुंच, सामर्थ्य और विश्वास में सुधार करके रोगियों को काफी लाभ होगा।

एआईआईए टीम को बधाई देते

राज्यसभा में सत शर्मा ने उठाए जम्मू-कश्मीर के शहरी परिवहन और ग्रामीण आजीविका से जुड़े अहम मुद्दे

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : जम्मू–कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा सीए ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में जम्मू–कश्मीर से जुड़े जनहित के दो महत्वपूर्ण विषयोंकृशहरी परिवहन व्यवस्था और ग्रामीण आजीविका सृजनकृको मजबूती से उठाया। उन्होंने इन मुद्दों पर केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की और यह स्पष्ट किया कि क्षेत्र के संतुलित और समावेशी विकास के लिए शहरी एवं ग्रामीण दोनों स्तरों पर ठोस और दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है।

सत शर्मा ने सदन में एक अतारांकित प्रश्न के माध्यम से जम्मू शहर के लिए तैयार किए गए समग्र मोबिलिटी प्लान (कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान) से संबंधित जानकारी मांगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू जैसे तेजी से बढ़ते शहर में यातायात जाम, प्रदूषण, सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन की सीमित उपलब्धता जैसी समस्याएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं। ऐसे में एक ऐसी परिवहन व्यवस्था की जरूरत है जो टिकाऊ, एकीकृत और भविष्य की आवश्यकताआ. ें के अनुरूप हो।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने सदन को बताया कि जम्मू शहर के लिए समग्र मोबिलिटी प्लान को एक दीर्घकालिक और एकीकृत शहरी परिवहन ढांचे के रूप में तैयार किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, यातायात जाम और कार्बन उत्सर्जन को कम करना, सड़क सुरक्षा में सुधार करना, विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना है।

मंत्री ने आगे जानकारी दी कि इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अल्पकालिक चरण में यातायात प्रबंधन को बेहतर

बनाने, बस सेवाओं को मजबूत करने और मौजूदा बुनियादी ढांचे के कुशल उपयोग पर ध्यान दिया जाएगा।

मध्यम अवधि में सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार और स्मार्ट ट्रैफिक समाधान लागू करने की योजना है, जबकि दीर्घकालिक चरण में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे आधुनिक परिवहन विकल्पों की शुरुआत का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त, जम्मू शहर में शहरी परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री ई–बस सेवा योजना के तहत 100 बसों को स्वीकृति दी गई है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर और सुलभ परिवहन सुविधा मिल सकेगी।

इसके साथ ही सत शर्मा ने जम्मू–कश्मीर में खादी और ग्रामोद्योग के विकास से जुड़े मुद्दे को भी सदन में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्रों में स्थापित क्लस्टरों, वित्तीय सहायता और रोजगार सृजन की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि केंद्र सरकार की स्फूर्ति योजना के तहत जम्मू–कश्मीर में खादी और ग्रामोद्योग के छह क्लस्टर वर्तमान में कार्यान्वयन की अवस्था में हैं।

मंत्री ने बताया कि ये क्लस्टर रामबन, डोडा, सांबा, बारामूला, पुलवामा और श्रीनगर जैसे जिलों में स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को संगठित करना, पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत छ501.64 लाख की राशि स्वीकृत और जारी की गई है, जिसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। इस वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं, जिनका लाभ विशेष रूप से महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कारीगरों को मिला है।

सत शर्मा ने कहा कि शहरी परिवहन और ग्रामीण उद्योग दोनों ही जम्मू–कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बेहतर शहरी मोबिलिटी जहां नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारती है, वहीं खादी और ग्रामोद्योग जैसे पारंपरिक क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और स्थायी आजीविका का मजबूत आधार प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य केवल बुनियादी ढांचे का विकास नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाना है। अंत में सत शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य में उनके प्रभावी क्रियान्वयन से जम्मू–कश्मीर में समावेशी विकास को गति मिलेगी, शहरी जीवन अधिक सुव्यवस्थित होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रतिबद्धता है कि जम्मू–कश्मीर को विकास, अवसर और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाया जाए।

जम्मू में स्वच्छता अभियान तेज, नगर निगम ने 100 से अधिक अस्वच्छ झुग्गियां ध्वस्त कीं

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और खुले में शौच मुक्त बनाने की दिशा में जम्मू नगर निगम ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक अस्वच्छ झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया है। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई जन स्वास्थ्य की रक्षा, पर्यावरणीय स्वच्छता सुनिश्चित करने और शहरी स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई है। यह अभियान नगर आयुक्त देवांश यादव के निर्देशों के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में चलाया गया, जहां लंबे समय से अस्वच्छ और अनधिकृत झुग्गी बस्तियों की मौजूदगी को लेकर शिकायतें सामने आ रही थीं।

अधिकारी के अनुसार, यह व्यापक अभियान जग्गी दरबार, पलौरा, जानीपुर पुलिस स्टेशन के पास, लोअर रूपनगर और सुभाष नगर सहित कई क्षेत्रों में चलाया गया। इन इलाकों में ऐसी झुग्गी बस्तियों की पहचान की गई थी, जहां बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं का घोर अभाव था। न तो इन बस्तियों में उचित शौचालय व्यवस्था थी और न ही कचरा निपटान या स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध थीं। नगर निगम का मानना है कि इस तरह की परिस्थितियां न केवल वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी बीमारियों के फैलने का कारण बन सकती हैं। अभियान के दौरान नगर निगम की टीमों ने इन झुग्गियों को अस्वच्छ घोषित करते हुए उन्हें हटाने की कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि इन बस्तियों से निकलने वाला कचरा, गंदा पानी और खुले में शौच जैसी गतिविधियां जन स्वास्थ्य, पर्यावरणीय संतुलन और शहर की समग्र स्वच्छता के लिए गंभीर खतरा बन चुकी थीं। विशेष रूप से मानस. ून और गर्मियों के मौसम में ऐसी जगहों पर संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका और अधिक बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया।

नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये झुग्गियां न केवल अस्वच्छ थीं, बल्कि अनधिकृत भी थीं और नगर निगम के नियमों का उल्लंघन कर रही थीं। शहर में स्वच्छता और जन स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखने के लिए बनाए गए नियमों के तहत इस तरह के निर्माण की अनुमति नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते इन पर कार्रवाई नहीं की जाती, तो यह शहर के खुले में शौच मुक्त ढांचे को कमजोर कर सकती थीं। जम्मू को ओडीएफ बनाए रखने के लिए वर्षों से किए जा रहे प्रयासों पर इस तरह की बस्तियों के कारण प्रतिकूल असर पड़ रहा था।

नगर निगम का यह भी कहना है कि अस्वच्छ और अनधिकृत निर्माणों की संख्या में हाल के वर्षों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। कई बार लोग नियमों की अनदेखी कर अस्थायी ढांचे खड़े कर लेते हैं, जो धीरे–धीरे स्थायी झुग्गियों का रूप ले लेते हैं। इन बस्तियों में न तो स्वीकृत नक्शे होते हैं और न ही स्वच्छता से जुड़े किसी मानक का पालन किया जाता है। ऐसे में नगर निगम के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह समय–समय पर सख्त प्रवर्तन अभियान चलाकर स्थिति को नियंत्रित करे। अधिकारी ने यह भी बताया कि यह अभियान केवल एक बार की कार्रवाई नहीं है।

अस्वच्छ ढांचों के तेजी से बढ़ते निर्माण को रोकने और स्वच्छता नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में जम्मू शहर के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के विध्वंस और प्रवर्तन अभियान जारी रहेंगे।

नगर निगम ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भविष्य में भी जहां कहीं नियमों का उल्लंघन करते हुए अस्वच्छ झुग्गियां या ढांचे पाए जाएंगे, वहां बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी।

इस अभियान के दौरान नगर निगम ने अन्य संबंधित विभागों के साथ भी समन्वय किया, ताकि किसी भी तरह की कानून–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। पुलिस और अन्य एजेंसियों की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिससे प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई से पहले संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया था और नियमों के अनुसार आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया।

स्वच्छ, स्वस्थ और ओडीएफ–अनुरूप जम्मू के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए जम्मू नगर निगम ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। निगम ने कहा है कि शहर की स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों की भी समान भागीदारी आवश्यक है। यदि लोग स्वच्छता मानदंडों का पालन करें, खुले में कचरा न फेंकें और अनधिकृत निर्माण से बचें, तो शहर को साफ और रहने योग्य बनाए रखना कहीं आसान हो सकता है।

नगर निगम ने यह भी अपील की है कि किसी भी क्षेत्र में यदि अस्वच्छ या अनधिकृत झुग्गी बस्ती विकसित होती दिखे, तो नागरिक इसकी जानकारी तुरंत निगम को दें। समय रहते सूचना मिलने पर कार्रवाई करना आसान होता है और बड़े स्तर पर समस्या खड़ी होने से पहले ही उसे रोका जा सकता है। अधिकारियों का मानना है कि सामूहिक प्रयासों से ही जम्मू को एक आदर्श, स्वच्छ और स्वस्थ शहर के रूप में विकसित किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, जम्मू नगर निगम द्वारा चलाया गया यह अभियान शहर में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जहां एक ओर इससे जन स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर यह संदेश भी जाएगा कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में इस तरह के और अभियानों के जरिए नगर निगम जम्मू को स्वच्छ, स्वस्थ और ओडीएफ–अनुरूप बनाए रखने के अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार प्रयास करता रहेगा।

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

मिनी हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध ऐरवा तीर्थ स्थल पर महा शिवरात्रि महोत्सव शुरू, विधायक व जिला आयुक्त ने किया उद्घाटन

दो दिवसीय किसान मेला, खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, खिलाड़ियों को किया सम्मानित

सबका जम्मू कश्मीर

ऐरवा/नगरी/कठुआ : हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिनी हरिद्वार के नाम से चर्चित ऐरवा तीर्थ स्थल पर ऐरवा मंदिर कमेटी की ओर से दो दिवसीय महा शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कठुआ विधायक डॉ भारत भूषण व जिला आयुक्त द्वारा किया गया।

उद्घाटन से पहले विधायक और जिला आयुक्त ने खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थल पर पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। इसके बाद दोनों अतिथियों ने किसान मेले का भी दौरा किया, जहां विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की।

मंदिर कमेटी की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डोगरी संस्कृति और परंपरा को विशेष प्राथमिकता दी गई। खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया।

कमेटी सदस्यों ने प्रशासन और विधायक द्वारा किए गए विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले समय में इन योजनाओं को जमीन पर उतारा जाएगा। इस मौके पर कमेटी सदस्य डॉ हरीदत शिशु ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शाम को विधि–विधान से गंगा आरती भी आयोजित की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग शामिल होते हैं।

कार्यक्रम में जिला आयुक्त, ऐरवा के चेयरमैन, अना जमवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे।

जम्मू–कश्मीर बजट : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल्याण और विकास उपायों की घोषणा की

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को 2026–27 के बजट में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत करने और केंद्र शासित प्रदेश में सतत विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी उपायों और विकास पहलों की घोषणा की।

बजट विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है, जिसमें रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया है। 1.27 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, सरकार ने अनुसंधान, उद्यमिता और उच्च स्तरीय वैज्ञानिक नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए कठुआ और हंदवारा बायोटेक पार्कों के पुनरुद्धार की घोषणा की है। उन्होंने कहा, बजट में किसानों के लिए सौर पंप, सरकारी भवनों का सौर ऊर्जा से संचालन, लघु जलविद्युत परियोजनाएं और आदिवासी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से चलने वाले गांवों की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

अनुसंधान और विकास के लिए सहायता, पीएचडी स्तर तक छात्रवृत्ति और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार की भी घोषणा की गई।

अर्थव्यवस्था और हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, अब्दुल्ला ने यूनिटी मॉल को एक स्थायी हस्तशिल्प बाजार के रूप में स्थापित करने और राष्ट्रीय और वैश्विक क्रेता–विक्रेता बैठकों के माध्यम से जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन (जेकेटीपीओ) की पहुंच बढ़ाने की घोषणा की। सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधार–आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के साथ स्पर्श प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, बजट में श्री अमरनाथ जी यात्रा के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 180 करोड़ रुपये और दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन राशि शामिल है।

सामाजिक कल्याण क्षेत्र में, मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कक्षा 9 से कॉलेज स्तर तक के छात्रों के लिए पूर्ण शुल्क माफी और पात्र परिवारों के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए मासिक प्रायोजन सहायता, आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त सरकारी परिवहन सुविधाओं का भी प्रस्ताव रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, बजट में सेब, केसर, आम और लीची की फसलों के लिए फसल बीमा कवरेज और कम सुविधा वाले जिलों में नियंत्रित वातावरण भंडारण सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, "सरकार सूक्ष्म और स्प्रिंकलर सिंचाई, सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने और पशुधन के आनुवंशिकी में सुधार के लिए प्रत्येक जिले में भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बना रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त दर्जा प्राप्त करने के लिए भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।"

शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए इंटरनेट की आवश्यकता के बिना जम्मू–कश्मीर ई–पाठशाला डीटीएच चैनल, आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक बाल विद्यालयों में उन्नत करने, सभी सरकारी स्कूलों में इनडोर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने और सरकारी रियायतों का लाभ उठाने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती देने का प्रस्ताव रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में लाल डेड अस्पताल का विस्तार किया जाएगा, जिसमें आईवीएफ और एनआईसीयू सुविधाएं होंगी और जीएमसी अनंतनाग में एक नया मातृ एवं शिशु अस्पताल स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "सरकार ने राजौरी, बारामूला और डोडा में कैथ लैब, उरी और पुंछ में आपातकालीन अस्पताल, नीति आयोग और आईसीएमआर के सहयोग से जम्मू–कश्मीर–व्यापी कैंसर नियंत्रण रणनीति और सीमावर्ती जिलों के लिए बुलेटप्रूफ एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना, सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करना और जम्मू–कश्मीर में आर्थिक विकास को गति देना है।

साप्ताहिक राशिफल

मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी कभी गम लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपक.ो निजी जीवन से लेकर करियर–कारोबार तक में उतार–चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहने वाली है। इस दौरान व्यक्तिगत और पेशेवेर रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज–मस्ती करते हुए बीतेगा। घर–परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सप्ताह के मध्य में आपको करियर–कारोबार में कुछ अप्रत्याशित बदलाव को झेलना पड़ सकता है।

इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता रहेगी।

वृषभ

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। वृष राशि के जो जातक किसी कार्य विशेष के लिए बीते कुछ समय से लगातार प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह भी उससे जुड़ी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले उनका पूर्वार्ध थोड़ा राहत भरा रहने वाला है।

ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने करियर–कारोबार और जीवन से जुड़े अहम कार्यों को इसी दौरान करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से मेल–मुलाकात होगी। जिसकी मदद से अटके कार्यों में धीमी गति से ही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में न सिर्फ कार्यक्षेत्र से जुड़ी बल्कि घर–परिवार से संबंधित समस्याएं भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी जमीन–जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। अचानक से जीवन में तमाम तरह की समस्याएं सामने आने से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस दौरान आपके संगी–साथी आपकी ढाल बनेंगे और आपके साथ साए की तरह बने रहेंगे।

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो उम्मीद का दामन बिल्कुल न छोड़ें क्योंकि इस सप्ताह उसमें आ रही बाधाएं स्वतरू दूर होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है।

इस दौरान आपके शुभचिंतक आपको नेक सलाह देते हुए नजर आएंगे, जिस पर अमल करके आप अपनी चीजों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। इस पूरे सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक–कार्यों में खूब रमेगा। किसी धार्मिक–आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुक.ाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप आप समझदारी के साथ अपने पैसे का सही जगह निवेश करते हैं तो आपको उससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आएगा।

कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक.ों को किसी भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। रिश्ते–नाते में मिठास बनी रहे और किसी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो इसके लिए स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखें।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार के सिलसिले में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलें। यदि कार्यक्षेत्र पर हालात आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप उससे बजाय भागने के उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। भूलकर भी आवेश में आकर नौकरी में बदलाव जैसा फैसला लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याओं के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको आपके विरोधी आप पर हावी होने तथा आपके बनते काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक.ों को अपनी ऊर्जा, धन और समय का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान कार्य विशेष के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर भी अचानक निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने कारोबार से जुड़े बड़े फैसले इसी दौरान करने चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप कुछ चीजों को लेकर खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। ऐसे में इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। नौकरीपेशा जातकों इस सप्ताह अपने कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से पूरे करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा पूर्व में की गई न सिर्फ आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट भी सुननी पड़ सकती है।

कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मनचाही सफलता और खुशियां मिले तो आपको अपने कार्य और व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा और अपने शुभचिंतकों को नाराज करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपकी किसी बात या व्यवहार से आपके अपने नाराज हो सकते हैं। वाद–विवाद बढ़ने पर वर्षों से बने रिश्ते में दरार आ सकती है। करियर–कारोबार से लेकर घर–परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहे इसके लिए दूसरों से अपेक्षा करने करने की बजाय आपको खुद ही आगे बढ़कर प्रयास करना होगा।

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में कनिष्ठ लोगों के साथ रुखा व्यवहार न करें और अपने वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो शार्टकट तरीके से लाभ कमाने से बचें और कागजी काम पूरे करके रखें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन सावधानी के साथ करें।

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम और रिश्ते–नाते की दृष्टि से मध्यम फलदायी रहने वाला है।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह तुला राशि का नौकरीपेशा जातक हो या फिर व्यवसाय से जुड़ा कारोबारी, वह अपना शत प्रतिशत अपने कार्य में देता हुआ नजर आएगा।

खास बात कि उसके प्रयासों को सौभाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और सीनियर आपके कामकाज की खुले मन से प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के अंत तक आपको बड़ा पद अथवा अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी नये कारोबार की शुरुआत करने अथवा किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी–रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभता–सफलता की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। करियर–कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यदि आपके कारोबार में बीते समय से कोई अड़चन आ रही थी इस सप्ताह वह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से दूर हो जाएगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आप उसके विस्तार की योजना पर काम करेंगे। आपकी योजना को साकार रूप देने के लिए आपके शुभचिंतक और परिजन पूरी मदद करेंगे। इस संबंध में घर–परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लाभदायी साबित होगी। यह सप्ताह पठन–पाठन एवं शोध से जुड़े कार्यों को करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा।

धनु

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन के नये अवसरों को लेकर आने वाला है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य और आशंका को त्याग कर कठिन परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस सप्ताह यदि आप अपने धन, समय और उर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आपको आशा से अधिक सफलता और लाभ मिल सकता हैं। वहीं इसकी अनदेखी करने पर बनते काम बिगड़ जाने से मन में निराशा के भाव जाग सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह खुले हाथ धन खर्च करने से बचना चाहिए अन्यथा सप्ताह के अंत तक उन्हें उधार मांगने की नौबत आ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको कारोबार में लाभ तो होगा लेकिन साथ ही साथ खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है। परीक्षा–प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है।

मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार–चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने करियर–कारोबार में आ रही अड़चनों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र और कारोबार के अलावा निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं भी आपकी बड़ी चिंता का कारण बनेंगी। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके शुभचिंतक एवं परिजन काफी मददगार साबित होंगे और काफी हद तक आप इन समस्याओं का समाधान खोजने में भी कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी भी कार्य को करते समय विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ बात–व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं अन्यथा लंबे समय से बने हुए रिश्तों में दरार आ सकती है। इस सप्ताह खर्च की अधि.कता के चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर–कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है।

कुंभ

जीवन में आने वाली छोटी–मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। करियर और कारोबार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे और आपके पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिर सकता है। सत्तापक्ष से जुड़े लोगों के साथ आपका मेल–मिलाप बढ़ेगा। आपके मान–सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपनी सूझबूझ से अपने विरोधियों पर काबू पाने में कामयाब होंगे। कुंभ राशि के जो जातक तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक का कारोबार करने वालों को बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति से कार्य विशेष के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

मीन

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय जहां अनुकूल तो वहीं उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों सप्ताह की शुरुआत में ही निबटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इसी दौरान पूरे मनोयोग से रोजी–रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से भूमि–भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकल सकता है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि उनकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ भी सकती है।

ऐसे में अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी न करें और सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके घर में कोई धार्मिक अथवा मांग.लिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा–पाठ में बीतेगा।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

टकराव की राजनीति, मुनाफाखोरी और विश्व शांति की आवश्यकता

आई. डी. खजुरिया

समकालीन विश्व एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ टकराव की राजनीति और अधिकतम लाभ कमाने की प्रवृत्ति ने वैश्विक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अनेक देशों में राजनीतिक नेतृत्व और बड़े कॉर्पोरेट समूहों के बीच बढ़ती नजदीकियों ने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं, जिनमें सामूहिक मानव हितों की बजाय निजी और आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति, सहयोग और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से जिन सिद्धांतों और नियमों को अंतरराष्ट्रीय सहमति से स्वीकार किया गया था, आज वे कई स्तरों पर चुनौती का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से न्दपजमक छंजपवदे (यूएनओ) के मंच पर पारित अनेक प्रस्तावों और समझौतों की अनदेखी विश्व व्यवस्था के लिए चिंता. जनक संकेत है।

आज विश्व के सामने पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापवृद्धि, मानवाधिकारों का हनन, महामारी जैसी बीमारियाँ, आर्थिक असमानता और देशों के बीच बढ़ते तनाव जैसी गंभीर चुनौतियाँ हैं। इन समस्याओं का समाधान किसी एक राष्ट्र या समूह के हितों से नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी से ही संभव है। दुर्भाग्य से, कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों और नेताओं द्वारा आक्रामक राष्ट्रवाद और शक्ति प्रदर्शन की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे शांति और संवाद की प्रक्रिया कमजोर पड़ती दिखाई देती है।

विश्व राजनीति में बढ़ती ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति ने आम जनता के बीच असुरक्षा और अविश्वास की भावना को जन्म दिया है। हथियारों की होड़, सैन्य बजट में वृद्धि और युद्धोन्मुख नीतियाँ न केवल संसाधनों की बर्बादी हैं, बल्कि मानवता के भविष्य के लिए भी खतरा हैं। जिन संसाधनों का उपयोग शिक्षा,

स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छ जल और खाद्य सुरक्षा के लिए किया जा सकता था, वे विनाशकारी साधनों पर खर्च हो रहे हैं। यह प्रवृत्ति मानव सभ्यता को विकास की बजाय विनाश की दिशा में ले जाती है।

ऐसे समय में विश्व के नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

लोकतांत्रिक समाजों की शक्ति जनता में निहित होती है, और जब नागरिक शांति, सह–अस्तित्व और पारस्परिक निर्भरता के मूल्यों को अपनाते हैं, तब राजनीतिक व्यवस्था भी उसी दिशा में बदलने को बाध्य होती है। चाहे वह ।उमतपबं हो या प्दकपं, जनता की जागरूकता और सहभागिता ही नीतियों को मानवता के हित में मोड़ सकती है। विश्व राजनीति में चर्चित नेताओं जैसे क्वदंसक ज्तनउच, छंतमदकतं डवकप, ग्प श्रपदचपदह और टसंकपउपत च्नजपद के संदर्भ में भी यह बहस उठती रही है कि वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए टकराव नहीं बल्कि संवाद और सहयोग की आवश्यकता है। इसी प्रकार सैन्य शक्तियों और संस्थाओं, जैसे च्मवचसमश्े स्पइमतंजपवद ।तउल, की भूमिका भी तब सकारात्मक बन सकती है जब उनका उद्देश्य शांति और स्थिरता को बनाए रखना हो।

नई विश्व व्यवस्था की अवधारणा तभी सार्थक हो सकती है जब वह युद्ध, हथियारों और वर्चस्व की राजनीति को अस्वीकार करे और मानव कल्याण को केंद्र में रखे। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व समुदाय मिलकर जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण छोड़े। इसके साथ ही, "सबके लिए भोजन", "हर व्यक्ति को रोजगार", "सुरक्षित पेयजल" और "सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ" जैसे लक्ष्य केवल आदर्श नहीं, बल्कि मानवा. धिकार के रूप में स्वीकार किए जाने चाहिए।

शांति की राजनीति का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता और दूरदर्शिता है। सहिष्णुता, स्वीकार्यता और विविधता का सम्मान ही वैश्विक समाज को स्थिर और समृद्ध बना सकता है। विभिन्न जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना ही वास्तविक प्रगति का आधार है। जब लोग स्वयं को केवल किसी एक देश का नागरिक नहीं, बल्कि वैश्विक समाज का सदस्य मानने लगते हैं, तब संघर्षों की जगह सहयोग और प्रतिस्पर्धा की जगह साझेदारी का भाव विकसित होता है।

आज समय की मांग है कि विश्व के लोग शांति की आवाज को मजबूत करें, युद्धों का विरोध करें और मानवता को विभाजन की राजनीति से ऊपर उठाने का प्रयास करें। यदि विश्व समुदाय सामूहिक रूप से शांति, सहयोग और पारस्परिक निर्भरता के सिद्धांतों को अपनाता है, तो एक ऐसा भविष्य संभव है जिसमें विकास और न्याय साथ–साथ चलें और मानव सभ्यता सुरक्षित, संतुलित और मानवीय दिशा में आगे बढ़े।

शांति को अपनाएँ कृ युद्धों का विरोध करें।

आई. डी. खजुरिया

Helpline

पुलिस स्टेशन	
बाग–ए–बहू	2459777
बख्शी नगर	2580102
बस स्टैंड	2575151
शहर	2543688
गांधी नगर	2430528
गंग्याल	2482019
नौबाद	2571332
पक्का डांगा	2548610
रेलवे स्टेशन	2472870
सैनिक कॉलोनी	2462212
सतवारी	2430364
चन्नी हिम्मत	2465164
ट्रांसपोर्ट नगर	2475444
त्रिकुटा नगर	2475133
गांधी नगर	2459660
एसएसपी शहर	2561578
एसपी शहर उत्तर	2547038
एसपी दक्षिण	2433778
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ	
इंडियन एयर लाइन्स	
शहर कार्यालय	2542735
एयर पोर्ट	2430449
जेट एयर वेज़	2453999
सिटी ऑफिस	2573399
रेलवे	
रेलवे पूछताछ	131, 132, 2476407
बुकिंग	2470318
आरक्षण	2470315
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्टेशन	
बख्शी नगर	2543557
गांधी नगर	2430786
कंपनी बाग	2542582
नया प्लॉट	2573429
पंजतीर्थी	2547537
दूरसंचार विभाग	
डायरेक्टरी पूछताछ	197
फॉल्ट रिपेयर	198
ट्रंक बुकिंग	180
बिलिंग शिकायत	2543896
जम्मू नगर पालिका	
जं. लाइन्स	2578503
प्रशासन अधिकारी	2542192
स्वास्थ्य अधिकारी	2547440
डाक सेवाएँ	
मुख्य डाकघर शहर	2543606
गाँधी नगर	2435863
अग्निशमन सेवाएँ	
नियंत्रण कक्ष	101,132, 2476407
शहर	2544263
गाँधी नगर	2457705
नहर	2554064
गंग्याल	2480026
रसोई गैस डीलर	
चिनाब गैस	2547633
गुलमौर गैस	2430835
जैकफेड	2548297
एचपी गैस	2578456
शिवांगी गैस	2577020
तवी गैस	2548455
पावर हाउस	
गाँधी नगर	2430180
नहर रोड	2554147
जानीपुर	2533828
नानक नगर	2430776
परेड	2542289
सतवारी कैंट	2452813
अस्पताल	
जीएमसी अस्पताल	2584290
एस.एम.जी.एस. अस्पताल	2547635
सी.डी. अस्पताल	2577064
डेंटल अस्पताल	2544670
गांधी नगर अस्पताल	2430041
सरवाल अस्पताल	2579402
जी.बी. पंत कैंट अस्पताल	2433500
आयुर्वेदिक कॉलेज	2543661
सी.आर.पी. अस्पताल	2591105
आचार्य श्री चंदर	2662536
मानसिक अस्पताल	2577444
स्वामी विवेकानंद	2547418
ब्लड बैंक	2547637
एम्बुलेंस	2584225, 2575364
एम्बुलेंस (रेड क्रॉस)	2543739
नर्सिंग होम	
मददन अस्पताल	2456727
मेडिकेयर	2435070
त्रिवेणी नर्सिंग होम	2452664
सुविधा नर्सिंग होम	2555965
अल. फिरदौस नर्सिंग होम	2545050
आस्था नर्सिंग होम	2576707
बी एन चौरिटेबल ट्रस्ट	2505310
चोपड़ा नर्सिंग होम	2573580
हरबंस सिंह मेम हॉस्पिटल	2541952
जीवन ज्योति	2576985
युद्धवीर नर्सिंग होम	2547821
मीडियाएड नर्सिंग होम	2466744
सीता नर्सिंग होम	2435007
विभूति नर्सिंग होम	2547969
रामेश्वर नर्सिंग होम	2580601
बी एन चेरिटेबल	2555631
महर्षि दयानंद	2545225

ग्राम तुषार और जैजैपुर के आरा मिल में हजारों ट्रैक्टर अवैध अर्जुन पेड़ को काटकर किया गया है भंडारण

वन विभाग के अधिकारियों पर सांठ गांठ करने का लग रहा आरोप कार्यवाही करने में छूट रहे विभाग के पसीने

सबका जम्मू कश्मीर

सत्ती : जिले के ग्राम पंचायत तुषार और जैजैपुर के आरा मिल में बड़े पैमाने पर अर्जुन पेड़ों की कथित अवैध कटाई कर भंडारण करने का मामला सामने आया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार हजारों ट्रैक्टर लकड़ी काटकर ग्राम तुषार और जैजैपुर स्थित आरा मिलों में भंडारण की जा रही है ग्रामीणों का आरोप है कि यह पूरा कारोबार लंबे समय से संचालित हो रहा है और इसमें संबंधित विभाग के कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत भी शामिल है।

ग्रामीणों का कहना है कि अर्जुन पेड़ पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा नियम निर्धारित किए गए हैं। इसके बावजूद खुलेआम कटाई और भंडारण किया जाना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि आरा मिल संचालक. ों द्वारा कुछ अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर इस गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे शासन को राजस्व हानि और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, दिन–रात ट्रैक्टरों के माध्यम से लकड़ी का परिवहन जारी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो क्षेत्र का हरित आवरण गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।

वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी संज्ञान में आई है और जांच के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, फिलहाल किसी ठोस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि अवैध कटाई और भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित आरा मिल संचालकों एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कितनी तत्परता दिखाता है और क्या जांच के बाद दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई होती है।

वार्ड नंबर 16 अपर शिवा नगर, कठुआ में गली व नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ

विधायक डॉ. भारत भूषण ने किया उद्घाटन, लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : कठुआ के वार्ड नंबर 16, अपर शिवा नगर में गली और नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ विधायक डॉ. भारत भूषण द्वारा किया गया।

इस कार्य की निविदा राशि 5.50 लाख रुपये थी, जबकि कार्य 3.50 लाख रुपये में आवंटित किया गया है।

इस मौके पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है और लोगों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

स्थानीय लोगों ने कार्य शुरू होने पर खुशी जताई और कहा कि इससे जल निकासी की समस्या में राहत मिलेगी तथा आने–जाने में सुविधा होगी।

अरिगाम सुल्तान पठरी, लोरन में पीसीपीजी बैठक, नशे के खिलाफ जागरूकता पर जोर

राजेश कुमार

पूँछ : डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूँछ ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अरिगाम सुल्तान पठरी, लोरन में पीसीपीजी (पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप) की बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना और पुलिस व जनता के बीच सहयोग बढ़ाना था।

बैठक में स्थानीय लोगों, बुजुर्गों, युवाओं और अन्य गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए गंभीर खतरा है और इससे शारी. रिक, मानसिक तथा सामाजिक नुकसान होता है।

पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे सतर्क रहें और नशे से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को इस बुराई से बचाया जा सके।

वरिष्ठ मूर्तिकार गणेश कुमार शर्मा को अंतरराष्ट्रीय मानद डॉक्टरेट से सम्मान

कला और संस्कृति के क्षेत्र में लंबे योगदान के लिए मिला सम्मान

सबका जम्मू कश्मीर

हीरानगर/कठुआ/जम्मू : प्रख्यात वरिष्ठ मूर्तिकार गणेश कुमार शर्मा को कला और संस्कृ ति के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित "इंटरनेशनल ऑनरेरी डॉक्टरेट विद ऑनर्स" से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान अल यामाम इंटरनेशनल अकादमी फॉर कल्चर एंड पीस , द सुप्रीम कौंसिल ऑफ़ अरब ट्राइबस फॉर कल्चर एंड पीस और इंडिपेंडेंट रिकॉन्सेलिएशन कमिटी द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया।

गणेश कुमार शर्मा पिछले 45 वर्षों से कला और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने देश–विदेश में कई कला प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों में भाग लिया है और अपनी रचनात्मक कला के माध्यम से प्रेम, शांति और सांस्कृतिक जागरूकता का संदेश दिया है।

देवर पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल, टेराकोटा तथा देवदार और शीशम की लकड़ी पर उनकी बनाई गई मूर्तियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराही गई हैं। उनकी कलाकृतियां प्रकृति और मानव जीवन से प्रेरित होती हैं और कई प्रतिष्ठित स्थानों पर प्रदर्शित की जा चुकी हैं।

गणेश कुमार शर्मा को इससे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें इंटरनेशनल सिमोन बोलिवार हिस्पानअमेरिकन अवॉर्ड, इंडिया जूरी इंटरनेशनल अवॉर्ड और फ़ेअथेर एंड एक्सटेंडर ह्यूमनिटी अकादमी से मिला मानद डॉक्टरेट शामिल है।

प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग जीएमसी राजौरी द्वारा अंतर दृष्टि 2026 सम्मेलन आयोजित, देशभर से विशेषज्ञ शामिल

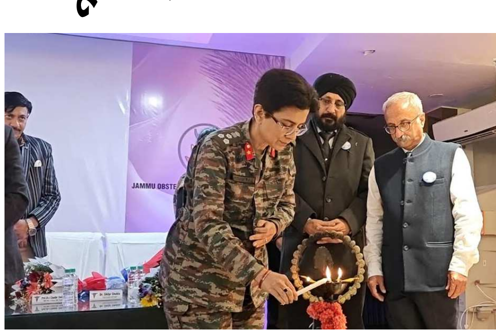

अनिल भारद्वाज

जम्मू/राजौरी : सरकारी मेडिकल कालेज संबंधित जिला अस्पताल राजौरी के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग द्वारा एसोसिएटेड अस्पताल में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं कार्यशाला अंतर दृष्टि 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर से आए प्रसिद्ध विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य महिला स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाना तथा आधुनिक उपचार पद्धतियों को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य प्रो. (डाक्टर) एएस भाटिया ने किया। ब्रिगेडियर डा. पूनम रॉय, कमांडेंट 150 जीएच (सेना अस्पताल) राजौरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। बड़ौदा (गुजरात) से प्रो. (डा.) देवेश शुक्ला विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल हुए।

इस अवसर पर डा. आर सी शर्मा (अध्यक्ष, जॉग्स जे एंड के), प्रो. (डा.) शिल्पी शुक्ला, प्रो. (डा.) चंदर शेखर (विभागाध्यक्ष एवं आयोजन अध्यक्ष), प्रो. (डा.) जमील–उल–हसन खान (विभागाध्यक्ष, मेडिसिन एवं अकादमिक अध्यक्ष) सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक, विभागाध्यक्ष, फैकल्टी सदस्य, पीजी छात्र और विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधि मौजूद रहे।

पहले दिन महिला स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें नई तकनीकों, जटिल गर्भावस्था प्रबंधन और आधुनिक स्त्री रोग उपचार पर चर्चा हुई।

दूसरे दिन एसोसिएटेड अस्पताल में लाइव लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

गाजियाबाद में सीनियर नेशनल फेडरेशन कप 2026 रचेगा इतिहास - महामंडलेश्वर यति नरसिंहनंद गिरी

शिव शक्ति धाम डासना में होगी भारत की सर्वोच्च कुश्ती प्रतियोगिता - छोटे नरसिंहनंद अनिल यादव

सबका जम्मू कश्मीर

गाजियाबाद : शिव शक्ति धाम डासना स्थित श्री कृष्ण योगधाम ट्रस्ट के तत्वाधान में 12, 13 एवं 14 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाला सीनियर नेशनल फेडरेशन कप 2026 गाजियाबाद के खेल इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है। यह प्रतियोगिता भारतीय कुश्ती संघ की भारत में होने वाली सर्वोच्च कुश्ती प्रतियोगिता मानी जाती है।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर यति नरसिंहनंद गिरि जी महाराज ने कहा कि यह आयोजन गाजियाबाद के युवाओं को खेलों से जोड़ने, उन्हें अनुशासित और संस्कारी जीवन की ओर प्रेरित करने का माध्यम बनेगा। खेल से जुड़े युवा नशे और व्यसनों से दूर रहते हैं। इस प्रतियोगिता से गाजियाबाद का नाम राष्ट्रीय पटल पर चमकेगा और यह आयोजन शहर के इतिहास में दर्ज होगा।

श्री कृष्ण योगधाम ट्रस्ट के सचिव अनिल यादव (छोटे नरसिंहनंद) ने बताया कि इस टूर्नामेंट में देशभर की सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर चुनी गई टॉप 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पहलवानों का चयन कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देशभर से लगभग 550 महिला एवं पुरुष खिलाड़ी भाग लेंगे।

गाजियाबाद कुश्ती एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजू पहलवान ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता शिव शक्ति धाम डासना स्थित श्री कृष्ण योगधाम ट्रस्ट के अत्याधुनिक रेसलिंग हॉल में आयोजित की जाएगी। 12 फरवरी 2026 को सभी खिलाड़ियों तथा भारतीय कुश्ती संघ के रेफरी और जजों के लिए आवास, भोजन एवं आवश्यक सुविधाओं की संपूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। आयोजन से संबंधित समस्त खर्चों का वहन भी श्री कृष्ण योगधाम ट्रस्ट करेगा।

गाजियाबाद कुश्ती एसोसिएशन के संरक्षक जयवीर पहलवान ने बताया कि 13 फरवरी 2026 को महिला एवं पुरुष वर्ग की फ्री स्टाइल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। महिला खिलाड़ियों की सभी प्रतियोगिताएं इसी दिन पूरी की जाएंगी। महिला वर्ग में ग्रीको-रोमन शैली शामिल नहीं होगी। 14 फरवरी 2026 को पुरुष वर्ग की शेष प्रतियोगिताएं भार वर्ग के अनुसार पूरी की जाएंगी, जिसमें खिलाड़ी फ्री स्टाइल, ग्रीको-रोमन और रोमन स्टाइल में अपना दमखम दिखाएंगे।

प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से बम्हैटा के खलीफा ब्रह्म यादव, सुदेश यादव, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पंकज मित्तल, उपाध्यक्ष पवन सिंघल, ट्रस्ट सदस्य सुदेश यादव, कोच शिव कुमार यादव, मोहित बजरंगी, लोकेश यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

तारिगामी ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अधिकारहीनता के खिलाफ झंडा उठाया, आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक और बहस की मांग की

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेता और विधायक एम.वाई. तारिगामी ने मंगलवार को जम्मू–कश्मीर विधानसभा की षक्तिहीनताष् पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि जनता का जनादेश मिलने के बावजूद, निर्वाचित प्रति. निधियों को अपने अधिकार का प्रयोग करने में कठिनाई हो रही है। मंगलवार को विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान, तारिगामी ने स्वीकार किया कि हालांकि अभिभाषण में सात साल बाद हुए विधानसभा चुनावों में मिले जनादेश की सराहना की गई, लेकिन जमीनी हकीकत यह दर्शाती है कि सदन को पर्याप्त अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उन्होंने कहा,

षमैंने उपराज्यपाल का आज का अभिभाषण पढ़ा, और हालांकि मैं इसकी प्रति अपने साथ नहीं ला सका, मेरे पास पिछले साल का अभिभाषण है। आज का अभिभाषण भी संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले साल, जब राज्यपाल ने पारंपरिक अभिभाषण दिया था, तो दो बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया थारू पहला, विधानसभा चुनावों में मिले जनादेश की सराहना; और दूसरा, कि ये चुनाव सात साल बाद हुए थे।ष्

चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ दृ माननीय उपराज्यपाल जहाँ कहीं भी हों, शायद उन्हें यह सुनना चाहिए दृ कि मंत्री आज बार–बार कहते हैं कि उनकी शक्तियाँ समाप्त हो गई हैं, लेकिन मुझे इससे भी अधिक दुख इस बात का है कि पूरा सदन कितना शक्तिहीन महसूस कर रहा है।"

सीपीआई (एम) नेता ने बताया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की बात न सुनने की धारणा सभी दलों में व्याप्त है और सत्ताधारी और विपक्षी दोनों पक्षों के सदस्यों द्वारा निजी तौर पर स्वीकार की जाती है। "यदि यह स्थिति बनी रहती है, तो केंद्र शासित प्रदेश का क्या अर्थ रह जाता है? यह किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है।

मैंने मुख्यमंत्री से बार–बार सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके कि ऐतिहासिक जनादेश के बावजूद विधानसभा को कमजोर क्यों किया जा रहा है और क्षेत्र को सशक्त क्यों नहीं बनाया जा रहा है," तारिगामी ने कहा।

उन्होंने जम्मू और कश्मीर में पारिस्थितिक संवेदनशीलता पर भी चिंता व्यक्त की और पर्यावरण संरक्षण पर अधिक ध्यान देने का आह्वान करते हुए क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को "अत्यंत नाजुक" बताया। उन्होंने कहा, "मैं मुख्यमंत्री से कुछ राज्यों की तर्ज पर एक अलग जलवायु बजट लाने का अनुरोध करता हूँ।"

जम्मू-कश्मीर सरकार आपदा प्रभावित भूमिहीन परिवारों को पट्टे पर जमीन आवंटित करेगी : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित भूमिहीन परिवारों को 40 साल के पट्टे पर पांच मरला (1.60 एकड़) जमीन आवंटित करने की मंजूरी दे दी है।

उन्होंने बताया कि उधमपुर जिले में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित 6,400 से अधिक परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

विधानसभा में भाजपा सदस्य बलवंत सिंह मनकोटिया के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया, जिसके बाद 2 जनवरी को एक सरक. ारी आदेश जारी किया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर में बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और भूकंप के कारण बेघर हुए प्रत्येक भूमिहीन परिवार को पांच मरला (1.60 एकड़) सरकारी जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी गई।

उन्होंने कहा कि यह जमीन आवासीय उद्देश्यों के लिए बिना किसी शुल्क के पट्टे पर दी जाएगी।

"लाभार्थियों को 40 वर्षों की अवधि के लिए 10 रुपये प्रति मरला का वार्षिक भू–किराया देना होगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है," उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवंटन सरकारी आदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

उन्होंने कहा कि उधमपुर जिले में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित 6,400 से अधिक परिवारों को 23.49 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

उन्होंने आगे कहा, "उधमपुर, चेनानी, रामनगर और लट्टी–मरोठी तहसीलों में कुल 6,449 प्रभावित परिवारों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुआवजा दिया गया।" उन्होंने कहा कि उधमपुर तहसील में 2,666 प्रभावित परिवारों को लगभग 9.32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जबकि चेनानी तहसील में 1,208 परिवारों को 5 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए।

रामनगर तहसील में 2,298 प्रभावित परिवारों को 7.8635 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जबकि लट्टी–मरोठी तहसील में 277 परिवारों को राहत सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनी टीमों द्वारा नुकसान का आकलन किया गया और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के मानदंडों के अनुसार पात्र मामलों का सत्यापन किया गया।

जम्मू-कश्मीर : मेहराज मलिक के पीएसए मामले में उच्च न्यायालय अगले सप्ताह दलीलें सुनेगा

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : जम्मू–कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय आम आदमी पार्टी (आप) विधायक महराज मलिक की लोक सुरक्षा अधि. नियम (पीएसए) के तहत हिरासत के समर्थन में जम्मू–कश्मीर प्रशासन की दलीलें 12 फरवरी को सुनेगा।

आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता मुदासिर हसन ने बताया कि न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की दलीलों का कुछ हिस्सा सुना और मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय की।

डोडा से विधायक मलिक को पिछले साल सितंबर में जन जागरूकता अधिनियम (पीएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

हरिया चक में दो ज्वेलरी दुकानों पर चोरी, 15-20 लाख का सामान पार; दुकानदारों ने किया रोड जाम

सबका जम्मू कश्मीर

मढीन : मढीन के साथ लगते गांव हरिया चक में बीती रात चोरों ने दो ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाकर इलाके में दहशत फैला दी। पीड़ित दुकानदारों के अनुसार चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और करीब 15 से 20 लाख रुपये के आभूषण व अन्य सामान लेकर फरार हो गए। घटना का पता सुबह तब चला जब दुकानदार रोज की तरह दुकान खोलने पहुंचे। शटर के ताले टूटे मिले और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था।

सूचना मिलते ही आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए।

घटना से नाराज हरिया चक के व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर रोड जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दुकानदारा. ें का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

सूचना मिलने पर मरीन चौकी के इंचार्ज गुलशन प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

उन्होंने स्थिति को संभालते हुए लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस ने जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया है।

मढीन चौकी को बड़ी सफलता, 25 गोवंशों को कराया मुक्त

सबका जम्मू कश्मीर

मढीन, मढीन क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मढीन चौकी इंचार्ज गुलशन प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रात के समय लगाए गए विशेष नाके के दौरान एक बंद बॉडी कंटेनर को रोका। तलाशी लेने पर कंटेनर के अंदर से 25 गोवंश बरामद किए गए, जिन्हें अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र से गोवंशों की तस्करी की जा सकती है। सूचना के आधार पर चौकी इंचार्ज ने टीम के साथ नाका लगाया और संदिग्ध कंटेनर को जांच के लिए रोका। कंटेनर खोलने पर अंदर ठूंस–ठूंस कर भरे गए 25 गोवंश मिले, जिन्हें तुरंत मुक्त कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर ही वाहन को अपने कब्जे में लेकर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तस्करों की तलाश जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने मढीन पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में पशु तस्करी पर लगाम लगेगी।

कठुआ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

6.75 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, मोटरसाइकिल भी जब्त

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कठुआ ने एक और नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 6.75 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) जैसी नशीली सामग्री बरामद की है।

पुलिस ने आरोपी की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के निर्देशन में की गई। 13 फरवरी को थाना कठुआ की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक को मोटरसाइकिल सहित रोका। पूछताछ और तलाशी के दौरान उसके पास से नशीला पदार्थ बरामद हुआ।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान रूपेश कुमार उर्फ बॉबी निवासी चक द्राब खान, तहसील व जिला कठुआ के रूप में हुई है। इस मामले में थाना कठुआ में एफआईआर नंबर 90/2026 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

जिला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नशे से जुड़ी किसी भी जानकारी को पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100, 112 या 9858034100 पर साझा करें। सूचना देने वाले की पहचान गोप. नीय रखी जाएगी।

मौजूदा चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है : सकीना इटू

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने आज कहा कि मौजूदा चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अतिरिक्त चिकित्सा ब्लॉकों का निर्माण आवश्यकता, व्यवहार्यता, मानव संसाधन और अवसंरचना की उपलब्धता के आधार पर ही किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने जम्मू–कश्मीर विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक शेख अहसान अहमद के चिकित्सा ब्लॉकों से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही।

मंत्री ने सदन को सूचित किया कि 15 लाख से अधिक आबादी वाले श्रीनगर जिले में वर्तमान में एक चिकित्सा ब्लॉक और चार चिकित्सा क्षेत्र हैं। ये चारों चिकित्सा क्षेत्र श्रीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रशास. निक नियंत्रण में कार्यरत हैं। उन्होंने आगे कहा कि श्रीनगर जिले में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रशासनिक, पर्यवेक्षी और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन मौजूदा मानव संसाधन और अवसंरचना के साथ सुचारू रूप से और संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है।

राजौरी में एएनएमटी स्कूल के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन

छात्रावास, स्टाफ व मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सड़क जाम

अनिल भारद्वाज

जम्मू/राजौरी : राजौरी स्थित एएनएमटी स्कूल के नर्सिंग स्ट्रीम के छात्रों ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न जायज मांगों को लेकर राजौरी नगर के अंतर्गत जवाहर नगर मुख्य सड़क मार्ग अवरुद्ध कर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि छात्रावास सुविधा की कमी, स्टाफ की भारी कमी, पीने के साफ पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर रोष व्यक्त किया।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर राजौरीदृबुद्धलदृकालाकोट मार्ग को जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहना. ें की लंबी कतारें लग गईं और आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब काफी समय तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। छात्रों का कहना था कि नर्सिंग जैसे महत्वपूर्ण कोर्स में पढ़ाई कर रहे छात्रों को आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। दूर–दराज के इलाकों से आने वाले छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास न होने के कारण उन्हें किराए के कमरों में रहना पड़ता है, जहां न तो सुरक्षा है और न ही उचित सुविधाएं। इसके अलावा स्टाफ की कमी के चलते पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस थाना राजौरी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस थाना प्रभारी हिलाल अजर ने छात्रों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर
"पत्रकारों की आवश्यकता"
'सबका जम्मू कश्मीर' हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र
के लिए जम्मू कश्मीर के सभी जिला के लिए पत्रकारों की आवश्यकता है इच्छुक पत्रकार संपर्क करें
योग्यता:
- पत्रकारिता में अनुभव
- उत्कृष्ट लेखन और संपादन कौशल
- सोशल मीडिया घराने में काम करने का अनुभव
अपना बायोडाटा ई.मेल करें
sabkajammukashmir@gmail.com
संपर्क नंबर :
6005134383

नाम परिवर्तन, तहसीलदार नोटिस, शोक संदेश, गुमशुदा सूचना, बेदखली, हुडा नोटिस, वैवाहिक, सार्वजनिक सूचना इत्यादि विज्ञापन
MOB:- +91 60051-34383, +91 87170 07205

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ कैंपस (जेयू) ने गोद लिए गांव कठेरा में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया

300 से अधिक छात्रों की भागीदारी, स्टेशनरी वितरण व पौधारोपण अभियान भी चलाया गया

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : कठुआ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ़ जम्मू द्वारा अपने गोद लिए गए गांव कठेरा में "स्कूली बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा" विषय पर छठा एक्सटेंशन आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में मान. सिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन, तनाव प्रबंधन और सकारात्मक सोच के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में 300 से अधिक छात्र, स्थानीय निवासी और फैकल्टी सदस्य शामिल हुए।

कार्यक्रम के दौरान स्टेशनरी वितरण अभियान–[illegible] भी चलाया गया, जिसके तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कठेरा के विद्यार्थियों को जरूरी शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। यह पहल विशेष रूप से हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित छात्रों की पढ़ाई को जारी रखने में मदद के लिए की गई।

इस अवसर पर एनएसएस कैंपस यूनिट–6 के स्वयंसेवकों ने गांव में पौधारोपण अभियान भी चलाया, ताकि पर्यावरण संरक्षण और बाढ़ के बाद प्राकृतिक संतुलन को मजबूत किया जा सके।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. अरविन्द जसरोटिया , रेक्टर, कठुआ कैंपस (जेयू) ने कहा कि कैंपस अपने गोद लिए गांव कठेरा के विकास के लिए लगातार काम करता रहेगा। उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों को बच्चों और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी बताया।

कार्यक्रम की शुरुआत में संयोजक डॉ. सौरभ शास्त्री ने अतिथियों का स्वागत किया और जागरूकता कार्यक्रमों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। डॉ. गौरव समनोत्रा , मनोरोग विभाग, जीएमसी कठुआने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जानकारी दी और तनाव से निपटने के आसान तरीके बताए। वहीं मेघा शर्मा मनोविज्ञान विभाग जीडीसी कठुआ ने बच्चों को भावनाओं को समझने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने के लिए प्रेरित किया।

कठुआ कैंपस के विद्यार्थियों ने इंजीनियर रितिका गुप्ता के मार्गदर्शन में मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित नाटक भी प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।

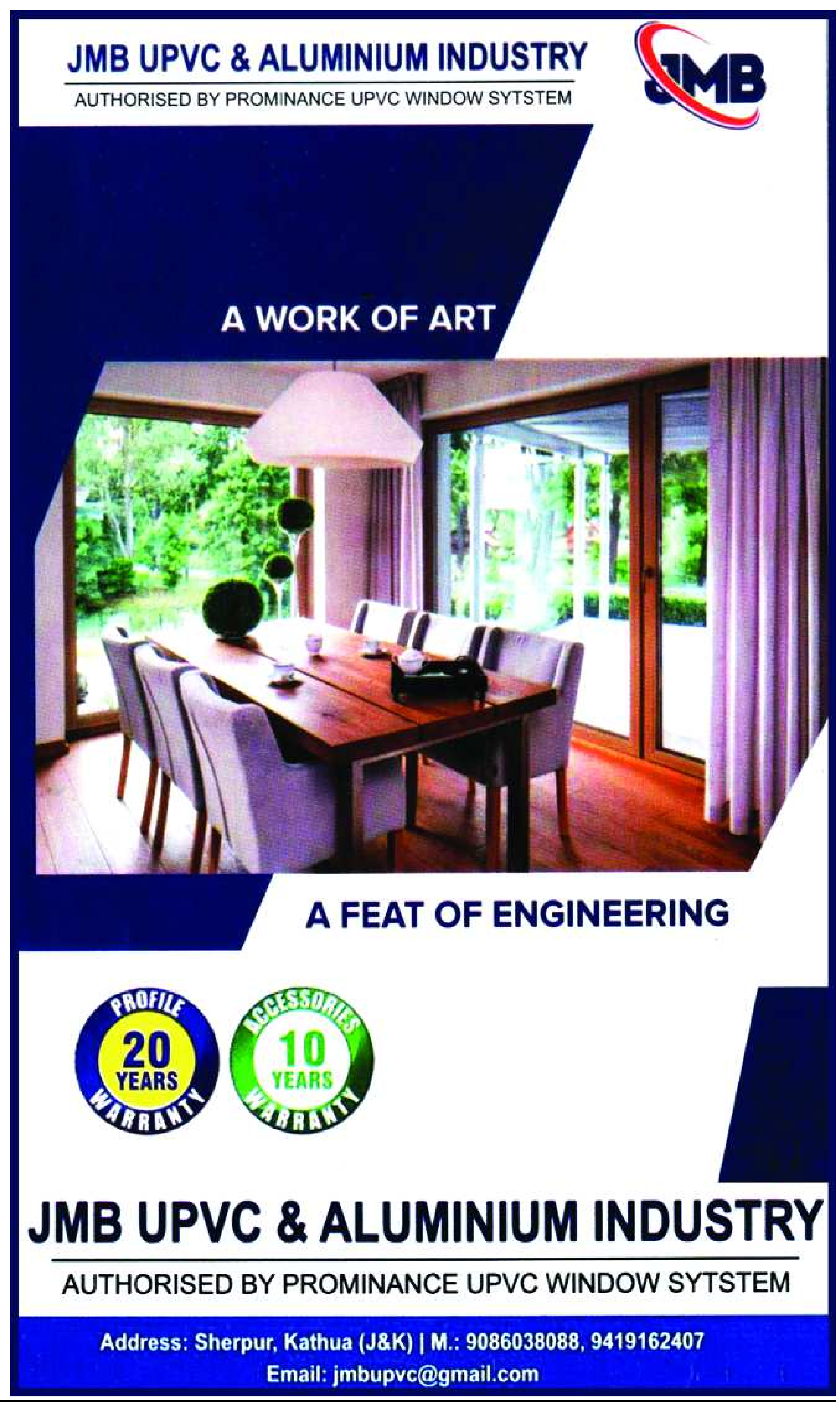

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशकः राज कुमार द्वारा एम/एस डी. आर प्रिंटिंग प्रेस, बैन बजाल्ता, तहसील जम्मू से मुद्रित एवं नगरी पैरोल नगरी, जिला कठुआ, जम्मू और कश्मीर पिन.कोड नंः 184151 । संपादकः राज कुमार